Email: jantantralive@gmail.com

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित

RNI NO-UPHIN/2010/36981

वर्ष: 13
अंक: 48
नई दिल्ली
सोमवार, 17 नवम्बर 2025
से रविवार, 23 नवम्बर 2025
पृष्ठ:- 8
मूल्य :- 2 ₹

जनतंत्र लाइव

Editor: Rajesh Yadav — बेबाक और बुलंद आवाज

जनतंत्र लाइव से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9212526181 पेज-8 www.jantantralive.com YouTube jantantralive

आरक्षण में क्रीमी लेयर पर चीफ जस्टिस गवई का बड़ा बयान

आईएएस के बच्चों की तुलना गरीब व मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती

अमरावती। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी।आर। गवई ने रविवार को कहा कि वह अब भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने के पक्ष में अभी भी बने हुए हैं। '75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान' नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गवई ने कहा कि आरक्षण के मामले में आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब कृषि मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गवई ने कहा, "मैंने आगे बढ़कर यह विचार रखा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा, जैसा कि इंद्रा साहनी (बनाम भारत संघ एवं अन्य) के फैसले में पाया गया है, लागू होनी चाहिए। जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू है, उसे अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।हालांकि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक आलोचना हुई है।" न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा, "लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि न्यायाधीशों से सामान्यतः अपने निर्णयों को उचित ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और मेरी सेवानिवृत्ति में अभी भी लगभग एक सप्ताह का समय है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में समानता या महिला सशक्तिकरण की गति बढ़ रही है और उनके साथ होने वाले भेदभाव की कड़ी आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले, उन्होंने जो अंतिम समारोह में भाग लिया वह फिर से आंध्र प्रदेश के अमरावती में था, जबकि सीजेआई बनने के बाद पहला समारोह महाराष्ट्र में उनके पैतृक स्थान अमरावती में था। न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और

अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि भारतीय संविधान 'स्थिर' नहीं है। डॉ0 बीआर अंबेडकर का हमेशा यह मानना था कि इसे विकसित, जैविक और अत्याधुनिक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा, "एक ओर डॉ। अंबेडकर की आलोचना की गई कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियां बहुत उदार हैं, और दूसरी ओर, यह आलोचना की गई कि कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों और संसद के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से संशोधन करना कठिन था।₹उनके अनुसार, संविधान सभा में संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने के दौरान डॉ। अंबेडकर के भाषण सबसे महत्वपूर्ण भाषण हैं, जिन्हें कानून के प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए।" आंबेडकर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बिना समानता, मनुष्य के जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रोत्साहन को समाप्त कर देगी और केवल स्वतंत्रता ही शक्तिशाली को कमजोर पर प्रभुत्व प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही भारत में अनुसूचित जाति से दो राष्ट्रपति हुए हैं और वर्तमान राष्ट्रपति भी अनुसूचित जनजाति की महिला हैं। गवई ने कहा, ₹अमरावती के अर्ध-झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में स्थित एक नगरपालिका स्कूल से प्राप्त एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, मैं न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक पहुंच सका और राष्ट्र निर्माण में अपने विनम्र तरीके से योगदान दे सका, केवल भारत के संविधान के कारण।₹ उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के चार स्तंभों पर खड़ा है।

हर चुनावी हार के बाद राहुल गांधी को दोष देना बना फैशनः राजीव शुक्ला

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कमी के दावों को खारिज करते हुए, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा सत्ता और संसाधनों के कथित दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और सभी वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए गए। शुक्ला ने कहा कि कुछ लोगों ने राहुल गांधी को दोष देना शुरू कर दिया है। हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान, प्रदर्शन इतना अच्छा था और सरकार लगभग बन ही गई थी, हर कोई राहुल गांधी की तारीफ कर रहा था। उन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा निकाली। वे हर जगह गए। प्रियंका गांधी भी नियमित रूप से गईं। खड़गे जी अपनी उम्र के बावजूद प्रचार करने गए। वेणुगोपाल जी भी दर्जनों बार वहाँ गए। तो ऐसा नहीं है कि प्रयास में कोई कमी थी। हर संभव प्रयास किया गया। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए शुक्ला ने जोर देकर कहा कि जब धन और शक्ति का इस्तेमाल हो रहा हो, तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है।

यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म

- बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन देगी योगी सरकार
- 60 साल पूरा होते ही खाते में आने लगेगा धन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी ह्यएक परिवार-एक पहचानह्ण प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि नई व्यवस्था में फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार होगी, जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है। यह सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी। विभाग सबसे पहले एसएमएस, व्हाट्सऐप और फोन कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से पात्र नागरिकों से सहमति लेगा। जिनकी सहमति डिजिटल रूप से नहीं मिलेगी, उनसे ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। दोनों स्तरों पर सहमति न मिलने पर ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करेंगे और स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा।

कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, भाजपा से नहीं डरतेः अखिलेश

लखनऊ। कर्नाटक में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बावजूद कांग्रेस पार्टी से अपनी सहानुभूति जताई और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कर्नाटक में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस एक मित्रवत पार्टी है और वह हमेशा उनके सहयोगी के रूप में रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि "मैं नाता जुड़ने के बाद उसे निभाना जानता हूं और बीजेपी या केंद्र सरकार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।" अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा, "मैं एक कांग्रेस नेता के घर के ठीक सामने खड़ा हूं, बीजेपी जो चाहे कह सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुश्किल समय में अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि दोस्त जब कमजोर हो, उसका साथ नहीं छोड़ते।"

गाजियाबाद के विकास को गति देने के लिए जीडीए और नगर निगम ने मिलाया हाथ

- जीडीए वीसी नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने मिलकर काम करने की बनाई योजना

गाजियाबाद। शहर के विकास और लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के वीसी नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने की। इसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। बैठक का मुख्य मकसद था कि प्राधिकरण की चार बड़ी योजनाओं को अब नगर निगम को सौंप दिया जाए ताकि उनकी देखभाल ठीक से हो सके। ये चार योजनाएँ थीं। गोविंदपुरम की कपूरीपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम, प्रताप विहार की भावराव देवरस योजना, और राजनगर एक्सटेंशन मुख्य सड़क का सेंट्रल

वर्ज (बीच का डिवाइडर)। इन योजनाओं को नगर निगम को सौंपने की रणनीति पर विस्तार से बात हुई।

योजनाओं को हैंडओवर करने की तैयारी: बैठक में तय किया गया कि इन योजनाओं को सौंपने से पहले, दोनों विभागों के अधिकारी मिलकर इन इलाकों का निरीक्षण करेंगे। वे देखेंगे कि अभी वहाँ कैसी स्थिति है और 10 दिन के अंदर उसकी एक रिपोर्ट और खर्च का अनुमान (एस्टीमेट) तैयार करके देंगे। इसके अलावा, इंदिरापुरम की एक बड़ी सीवर समस्या पर भी चर्चा हुई। नगर निगम ने प्राधिकरण से सीवर नेटवर्क का पूरा नक्शा मांगा, जिस पर प्राधिकरण वीसी ने तुरंत अधिकारियों को वह प्लान सौंपने का निर्देश दिया। कचरा प्रबंधन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए भी एक जरूरी कदम उठाया गयाः नगर निगम को 8000 वर्गमीटर जमीन एक सप्ताह के भीतर देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद हैंडओवर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इंदिरापुरम के ड्रोन सर्वे और टैक्स से जुड़ी जानकारी भी नगर निगम को देने पर सहमति बनी।

ट्रैफिक जाम से मिलेगा ऑफर: इस महत्वपूर्ण बैठक में आरडीसी क्षेत्र (राज नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर) में ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या पर भी ध्यान दिया गया। इस समस्या को खत्म करने के लिए एक खास योजना तैयार की गई, ताकि आरडीसी के लोगों को जाम से राहत मिल सके। नगर निगम और प्राधिकरण दोनों मिलकर इस क्षेत्र में सुधार के जरूरी काम करेंगे। दोनों विभागों के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि शहर के विकास के कामों को तेजी देने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है।

काम शुरू करने पर बनी सहमतिः बैठक में दोनों विभागों के कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने शहर के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। उन्होंने फैसला लिया कि बैठक में लिए गए कई जरूरी और महत्वपूर्ण निर्णय अगले 10 दिनों के अंदर जमीन पर दिखाई देने लगेंगे। यानी, जल्द ही शहर के विकास कार्यों में तेज आएगी, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। यह बैठक शहर के समग्र और तेज विकास के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हुई।

गाजियाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउन्सर्स की दबंगई पर डीएम की नकेल

- लोगों को भ्रमित करने वाली पौशाक न पहनें सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसरः जिलाधिकारी

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द कुमार माँदड़ ने शुक्रवार को कहा कि जनपदवासियों के जीवन की रक्षा करना, उन्हें भयमुक्त वातावरण प्रदान करना तथा सभी के न्याय की रक्षा करना जिला प्रशासन का दायित्व है। जनता दर्शन के दौरान अक्सर शिकायतें मिल रही है कि विभिन्न आरडब्लूए, एओए, विकासकर्ता व निजी व्यक्तियों ने सिक्योरिटी गार्ड और बाउन्सर्स रखे है, जो भिन्न-भिन्न प्रकार की वर्दी पहनते है तथा सोसाईटी और अन्य तमाम जगहों पर साथ में रहकर लोगों को डराते धमकाते है एवं जनसामान्य में भय का माहौल पैदा करते है। इस तरह का बर्ताव किसी भी तरह स्वीकार योग्य नही है। डीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसरों को लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और निर्देशित भी किया जा। सभी सिक्योरिटी गार्ड और बाउन्सर्स भी ध्यान रखें कि उनका बर्ताव लोगों के प्रति सम्मानपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण हो। उनके द्वारा पहने जाने वाली पौशाक शालीन हो। उनके द्वारा पहने जाने वाली पौशाक ऐसी न हो जो जनता को यह दिग्भ्रमित करें कि उक्त सेक्योरिटी गार्ड अथवा बाउन्सर्स पुलिस या सैन्य बल का सदस्य है। जिलाधिकारी ने सख्ती से कहा कि अगर आरडब्लूए, एओए, विकासकर्ता, निजी व्यक्तियों अथवा सिक्योरिटी गार्ड बाउन्सर्स द्वारा किसी जनमानस के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की अथवा उपरोक्त निदेर्शों से इतर बर्ताव की कोई भी शिकायत संज्ञान में लायी जाती है तो कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

दिल्ली के हैदरपुर पहुंची रेजांगला रज कलश यात्रा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता, वीर अहीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए

सीएम का ऐलान- दिल्ली में मेट्रो के तीन स्टेशनों का बदलेगा नाम

नई दिल्ली। लद्दाख से हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा कर रेजांगला युद्ध के वीर शहीदों के सम्मान में निकली पवित्र रज कलश यात्रा रविवार को दिल्ली के हैदरपुर पहुंची जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहुंचकर रज कलश यात्रा को प्रणाम किया और कहा कि इस यात्रा का हैदरपुर पहुंचना अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण है। रेजांगला शहीद पवित्र रज कलश यात्रा के हैदरपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा कि यह पवित्र यात्रा पूरे देश को राष्ट्र प्रथम की भावना में पिरोने वाला एक सशक्त संदेश है। उन्होंने कहा कि यादव महासभा और सभी आयोजकों को साधुवाद जिन्होंने इस यात्रा को राष्ट्रीय चेतना का

स्वरूप दिया है। हैदरपुर गांव की यह धरती आज स्वयं को धन्य मान रही है कि वीर शहीदों की पवित्र स्मृति यहां पहुंची। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक के नाम से जाना जाएगा। प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन को उत्तरी पीतमपुरा/प्रशांत विहार नाम दिया गया है। हैदरपुर बादली मोड़ का नाम अब हैदरपुर गांव रखा गया है। मैक्स अस्पताल मार्ग के चौड़ीकरण और अंडरपास के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे यहां के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। हैदरपुर गांव विकसित दिल्ली की उस नई पहचान का प्रतीक बन रहा है, जिसमें परंपरा को सम्मान और आधुनिक सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है।

गाजियाबाद के थाना लोनी में वकील से मारपीट, एसीपी सहित 10 पुलिसवालों पर केस का आदेश

गाजियाबाद। लोनी थाने में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले में अदालत ने एसीपी सहित 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। अधिवक्ता नितिन का आरोप है कि सात जुलाई 2024 को वह दो पक्षों के झगड़े के दौरान अपने क्लाइंट की पैरवी के लिए लोनी थाने गए थे। वहां पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया और पैसे भी लूट लिए। आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठी एफआइआर दर्ज कर दी, जिसके कारण उन्हें जमानत करानी पड़ी। नितिन की शिकायत पर जांच के दौरान चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका को निलंबित किया गया, लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नितिन ने 10 पुलिसकर्मियों को आरोपित बनाते हुए अदालत में एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या प्रताप सिंह की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका विकास सिंह, उपनिरीक्षक नरेश कुमार, अनिल कुमार, अंकुश तोमर, सिपाही सचिन कुमार राठी, थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर कृष्ण कुमार मौर्य, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोनी और एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा पर मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।

27 तक लगेगा ट्रेड फेयर, दिल्ली पवेलियन में 49 स्टाल पर प्रदर्शित किए जा रहे उत्पाद

नई दिल्ली। भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू हुए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पवेलियन इस वर्ष भी नवाचार, महिला-शक्ति और स्थानीय उद्यमिता की चमक को बखूबी प्रदर्शित कर रहा है। सभी दिल्लीवासियों और आगंतुकों से आग्रह है कि दिल्ली पवेलियन अवश्य पधारें और अपने परिश्रम, कौशल और संघर्ष से पहचान बना रहीं मेहनतकश बहनों तथा स्थानीय उद्यमियों के उत्कृष्ट उत्पादों और प्रतिभा को प्रोत्साहित करें। दरअसल, इस बार दिल्ली पवेलियन को लाल किले की थीम पर बनाया गया है। बाहर से दिल्ली पवेलियन की जो बाउंड्री है उसके ऊपर लाल किले का डिजाइन बनाया गया है। पिछले सालों की तुलना में दिल्ली पवेलियन का स्पेस इस बार थोड़ा बड़ा है। हालांकि, इस बार दिल्ली के पवेलियन में पिछले साल के मुकाबले स्टॉल थोड़े कम हैं, लेकिन ओपन स्पेस ज्यादा दिया गया है ताकि लोगों को मूवमेंट करने में परेशानी ना हो।

इस बार दिल्ली पवेलियन में कुल 49 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, दिल्ली सरकार के विभाग और अन्य उद्यमियों को भी जगह दी गई है। दिल्ली के पवेलियन के अंदर घुसते ही रेवड़ी और गजक की दुकान से शुरूआत होती है। फिर अंदर रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल हैं। इसके अलावा यहां पर फैंसी गुलदस्ते और बुके से लेकर के तमाम तरह के गिफ्ट आइटम और तरह-तरह के अचार की भी स्टॉल है। इसके साथ ही दिल्ली पवेलियन में फैंसी बैग, पर्दे और बेडशीट से लेकर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भी स्टॉल हैं। इसके अलावा, हींग से बने हुए खाद्य पदार्थों के भी स्कटॉल यहां लगाए गए हैं। दिल्ली पवेलियन में अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थों को भी दशार्या गया है। हैंडीक्राफ्ट के भी कई स्टॉल लगाए गए हैं। यहां पर एक सतयुग ध्यान केंद्र के नाम से भी एक स्टॉल है जो लोगों को आध्यात्मिक और योग के बारे में जानकारी दे रहा है। नए-नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई स्टार्टअप को भी दिल्ली पवेलियन में जगह दी गई है। अफगानी ड्राई फ्रूट्स की स्टॉल लगाई गई हैं। इसके अलावा कई तरह के परफ्यूम के स्टाल भी यहां लगे हैं। बच्चों के खिलौने से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्टरीज बोर्ड का भी एक स्टॉल लगाया गया है। दिल्ली जेल डिपार्टमेंट से भी कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा भी एक स्टॉल को लगाया गया है, जहां पर दिल्ली सरकार की दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही स्कीम के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा, दिल्ली टूरिज्म का भी एक स्टॉल दिल्ली पवेलियन में लगा है, जो दिल्ली के टूरिस्ट स्पॉट के बारे में दर्शकों को जानकारी दे रहा है।

11 सदस्यीय डूसू कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव सितंबर में संपन्न होने के बाद अब 11 सदस्यीय डूसू कार्यकारिणी का चुनाव भी संपन्न हो गया। शुक्रवार देर शाम डूसू कार्यकारिणी के नतीजे भी आ गए। इस तरह से अब डूसू की टीम पूरी हो गई। 11 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव में छह प्रत्याशी एबीवीपी के जीते हैं। एबीवीपी की तरफ से अंकित, आर्य तंवर, सिद्धार्थ चौधरी, मोहित यादव, पार्थ त्यागी और जयदीप ने जीत दर्ज की। इन 11 पदों में से दो पद छात्राओं के लिए आरक्षित थे परंतु एक ही पद पर नामांकन होने से एक पद खाली रह गया। जबकि बाकी पदों पर अन्य संगठनों के प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त की है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कार्यकारी परिषद का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों की छात्रसंघ यूनियनों के अध्यक्षों और सेंट्रल काउंसिल के सदस्यों द्वारा मतदान के जरिए किया जाता है। यह चुनाव प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तय नियमों और पारदर्शी प्रणाली के अंतर्गत संपन्न होती है। एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि डीयू छात्र संघ के कार्यकारी परिषद के चुनाव में एबीवीपी 11 में से 6 पदों पर विजयी हुई है। यह हमारी छात्र हित के प्रति निष्ठा एवं प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मालूम हो कि डूसू कार्यकारिणी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि डूसू के चार अधिकारी और 11 ईसी की समिति डूसू के कार्यक्रम की दिशा तय करते हैं।

लालकिला ब्लास्ट के बाद दिल्ली-एनसीआर से सैकड़ों कश्मीरी छात्रों ने वापस जाना शुरू किया

पुलिस कर रही है छात्रों की प्रोफाइलिंग

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली-एनसीआर से सैकड़ों कश्मीरी छात्रों ने वापस जाना शुरू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स असोसिएशन ने कहा कि गुरुग्राम में पढ़ रहे कश्मीरी छात्र घर लौटने लगे हैं। असोसिएशन के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे लगभग 500 कश्मीरी छात्रों ने अपने घर वापस जाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और अन्य इलाकों में पुलिस कश्मीरी छात्रों की बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग कर रही है। साथ ही किरायेदार के तौर पर रहे कश्मीरी छात्रों से मकान मालिक अब सत्यापन से जुड़े दस्तावेज मांग रहे हैं। जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स असोसिएशन ने बताया कि पुलिस ने यूपी की एचबीटीयू यूनिवर्सिटी के 52 कश्मीरी छात्रों का विवरण मांगा था जो उन्हें मिल गया है। वे यह जांच कर रहे हैं कि हाल ही में आतंकी घटना के मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन और डॉ. आरिफ का इन छात्रों में से किसी से कोई संपर्क है तो नहीं या पहले कभी कोई संपर्क था या नहीं। असोसिएशन के मुताबिक पुलिस ने मेरठ जोन में पढ़ रहे करीब 600 कश्मीरी छात्रों के बैकग्राउंड की भी जांच शुरू कर दी है। मेरठ के सुभारती, शोभित यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न कॉलेजों में लगभग 200 कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं। असोसिएशन ने बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन से उन कश्मीरी छात्रों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है, जो छुट्टियों पर अपने घर गए हुए हैं।

दिल्ली में सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 'नमो रन' का आयोजन किया गया

हरी झंडी दिखाकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- कहा- हर खिलाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 'नमो रन' को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसमें दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक अरविंदर सिंह लवली भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "यह आयोजन सुरक्षित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को सड़क सुरक्षा से जोड़ने और इस दौड़ के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य बहुत सुंदर है। इस तरह की प्रतियोगिताएं सुरक्षित और विकसित दिल्ली की राह में बहुत लाभदायक होंगी।" उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियां भी बेहतरीन क्रिकेट खेलती हैं। हर खेल का अपना महत्व है और हर खिलाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह खेल प्रतियोगिता, यह दौड़ और इसमें आपकी भागीदारी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को और पूरी आयोजन टीम को सभी को एक साथ लाने के लिए मैं बधाई देती हूं।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां जीवन का एक नियमित हिस्सा बन जानी चाहिए। मैं यहां उपस्थित अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों को कम से कम एक खेल में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करें। खेल केवल जीवन जीने का एक तरीका नहीं हैं, ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि खेलों में शामिल बच्चों में स्वाभाविक रूप से एकाग्रता और अनुशासन विकसित होता है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह हर दिन लोगों के बीच रहती हैं और रोजाना दो-तीन सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने शायद दस सालों में भी जनता से इतनी मुलाकात नहीं की होगी। सीएम रेखा गुप्ता लोगों से इतना ज्यादा जुड़ी रहती हैं जितना कि कभी-कभी एक महीने में ही, जितना कि दूसरे लोग सालों में भी नहीं कर पाते।

दिल्ली के दुकानदारों को अब 21 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से मिली मुक्ति

एक्ट में किया गया बदलाव

नई दिल्ली। दिल्ली के दुकानदारों को अब 21 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्ति मिल गई है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 की धारा 5 में बदलाव किया है। अभी तक कोई दुकानदार अपनी दुकान सालों से करता आ रहा था, तो हर 21 वर्ष के अन्तराल पर उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता था। लेकिन अब एक्ट में बदलाव होने से नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो गई। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के क्रम में दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुगम और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जिसके तहत दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय ने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

वर्तमान में इस एक्ट में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रेशन की तिथि से हर 21 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण करना अनिवार्य था। दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस नवीनीकरण प्रणाली को हटाने का निर्णय व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूत करेगा। इस निर्णय को लेकर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में 21 साल बाद होने वाले नवीनीकरण की अनिवार्यता हटने से व्यापारियों को वास्तविक राहत मिलेगी। प्रक्रियाएं सरल होने से दिल्ली का व्यापारिक वातावरण और अधिक उद्यमी-अनुकूल बनेगा। दिल्ली सरकार का यह निर्णय पंजीकरण प्रक्रिया को वन-टाइम रजिस्ट्रेशन मॉडल की ओर ले जाएगा जिससे व्यापारियों को नवीनीकरण की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। यह कदम दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई गति, पारदर्शिता और मजबूती प्रदान करेगा तथा राजधानी के व्यापार एवं सेवा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा।

सफेद कालर के आतंकियों ने देश के भरोसे को तोड़ दिया!

राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है, क्योंकि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे आतंकवाद की भयावह परतें खुलती जा रही हैं। जिन खतरनाक खुलासों का पदार्फाश हो रहा है, वे सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि आतंक के बदलते स्वरूप की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। जो नया खुलासा हुआ है, निःसंदेह प्रत्येक देशवासी को दहशत में में डालने वाला है, क्योंकि आतंकी देश के एक एक या दो जगहों में नहीं, बल्कि 32 जगहों में धमाके करने वाले वाले थे। यह सोच कर ही रूह कांप जा रहा है कि अगर आतंकी अपने मनसूबे में कामयाब हो जाते, तो फिर क्या होता। इससे एक बात यह भी साफ हो जाती है कि आतंकी अपना नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इसके साथ यह साफ हो गया है कि अब आतंकवाद किसी सीमित दायरे का मुद्दा नहीं, बल्कि ऐसे व्हाइट कॉलर नेटवर्क का रूप ले चुका है जिसके तार देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, शिक्षण केंद्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग तक फैले हुए हैं।सफेद कोट और चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे से जुड़े करीब दस उच्च शिक्षा प्राप्त डिग्री धारी डॉक्टर अब तक इस आतंकी साजिश की कड़ी में लिप्त मिल चुके हैं इस वारदात ने पहली बार डॉक्टर जैसे पवित्र पेशे पर आम आदमी के विश्वास और भरोसे को मटियामेट कर दिया है। वहीं एक संप्रदाय विशेष पर भी विश्वास का संकट पैदा करने के हालात बनाने का नापाक काम किया है खासकर काश्मीर मुस्लिमों को अब देश दुनिया भर में शंका की नजर झेलनी होगी। आपको बता दें कि अभी तक की जांच में पता चला है कि साजिश करने वाले आतंकी देश भर के विभिन्न स्थानों पर तैतीस गाडियों में विस्फोट करने का षडयंत्र कर रहे थे पहले इस मामले में सिर्फ चार गाड़ियों की बात सामने आई थी, लेकिन जांच एजेंसियों के नए इनपुट ने आतंकियों की योजना की व्यापकता को उजागर कर दिया है। ये गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं, आतंक की चलती फिरती फैक्टरियां थीं- जिनमें आई 20, मारुति सुजुकी ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी पुरानी कारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन गाड़ियों को कई हाथों में ट्रांसफर किया गया था, ताकि पुलिस साजिशकताओं तक न पहुंच सके। यह तरीका आतंकियों की चालाकी के साथ-साथ उनके व्यापक नेटवर्क की पुष्टि करता है। जांच में सामने आया है कि यह पूरी पूरी साजिश 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर बदला लेने की नीयत नीयत से रची गई थी। 33 साल पुराने घटना का हवाला देकर आज भी देश को अस्थिर करने की कोशिशें जारी हैं, यह अपने आप में बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा पहले इस धमाके को शुरू में एक स्थानीय घटना माना जा रहा था, लेकिन अब इसके तार अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि यह साजिश किसी एक हमले तक सीमित नहीं थी, चल्कि देशभर में दहशत फैलाने की एक विस्तृत योजना का हिस्सा थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल ने न केवल हथियार और विस्फोटक जुटाए थे, बल्कि 32 कारों को आईईडी से लैस कर आत्मघाती धमाकों के लिए तैयार किया जा रहा था। यह संयोग नहीं है कि इन कारों का उपयोग 6 दिसंबर को,

बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर, विभिन्न जगहों पर धमाके करने के लिए होना था। कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया जाना था जिनमें सिर्फ दिल्ली में छह प्रमुख लोकेशन शामिल थीं। यह स्पष्ट संकेत है कि आतंकियों का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना नहीं, बल्कि देश को कई मोर्चों पर अस्थिर करना था। इस पूरी साजिश को और गंभीर बनाता है इसका अंतरराष्ट्रीय पहलू।

जांच एजेंसियों का मानना है कि तुर्किये में बैठे एक हैंडलर से उमर नवी लगातार संपर्क में था। हैंडलर का कोड नेम उकासा था। जांच में खुलासा हुआ है कि उमर 2022 में तुर्किये गया था, जहां उसने जैश-ए-मोहश्वमद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। टेलीग्राम से शुरू हुई बातचीत एन्क्रिप्टेड ऐप्स तक पहुंची, और वहीं कारों में विस्फोटक भरकर दिली और अयोध्या जैसे शहरों को दहलाने की साजिश रची गई। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, उकासा दिल्ली स्थित मॉड्यूल और प्रतिबंधित संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसारगजत उल हिंद के हैंडलरों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम करता था। अधिकारियों ने बताया कि यह साजिश 2022 की शुरूआत शुरूआत में तुर्की में रची गई थी, जहां उमर और तीन अन्य जो सभी पाकिस्तान समर्थित दो समूहों से जुड़े थे, वहां गए थे। उमर मार्च 2022 में तुर्किये गया था और दो हफ्ते अंकारा में रहा था। उकासा ने ही उन्हें सीक्रेट सेल बनाने और डिजिटल फुटप्रिंट से बचने का तरीका बताया था। कथित तौर पर इस ऑपरेशन के लिए तीन कारें, एक हुंडई आई 20, एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक मारुति ब्रेजा खरीदी गई थीं। स्ट है कि आतंकवादी नेटवर्क की गतिविधियां अब सीमापार फैले हुए संरचनात्मक सहयोग से चल रही हैं। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भारत में स्लीपर सेल का जाल पहले से अधिक गंभीर व खतरनाक रूप ले चुका है।ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह माना जा रहा था कि आतंकवादी संगठन भारत की धरती पर कोई बड़ा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इस घटना ने उस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। इस पूरी जांच का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह कैसे संभव हुआ कि आतंकियों को दिल्ली जैसे शहर में सहानुभूति के ठिकाने मिल सके ? कश्मीर में दशकों से कुछ क्षेत्रों में आतंकी नेटवर्किंग के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनता रहा है, जिससे आतंकियों को पनाह मिलती रही। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है।

ऐसे में यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है है कि आखिर आतंकियों ने यहां कैसे अपने नेटवर्क को सक्रिय किया और कैसे स्थानीय सहयोग हासिल किया? यह बात साफ दिखाती है कि सुरक्षा एजेंसियों को अब आतंकवाद के स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों आयामों को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जांच केवल आरोपियों को पकड़ने तक सीमित न रहे, बल्कि उससे आगे जाकर यह समझा जाए कि सिस्टम की ऐसी कौन-सी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर आतंकियों ने इतनी बड़ी साजिश को जन्म दिया। यह भी अत्यंत जरूरी है कि देश की सुरक्षा प्रणाली में ऐसी दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाए जो आतंकवाद को केवल जड़ से उखाड़े ही नहीं, बल्कि उसकी संभावनाओं को भी समाप्त कर दे। आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई केवल सुरक्षा एजेंसियों के बल पर नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और नागरिक समाज के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। सबसे अहम बात यह है कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। किसी भी समाज में आतंकवादी विचारधारा तभी पनपती है जब उसे स्थानीय समर्थन या सहानुभूति मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें सामाजिक रूप से अलग-थलग किया जाए। सुरक्षा रणनीति में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि भारत-विरोधी तत्व चाहे वे सक्रिय हों अथवा स्लीपर सेल को निष्प्रभावी करने के लिए बहु-स्तरीय योजना काम में लाई जाए। इसके तहत निगरानी तंत्र को आधुनिक तकनीक से लैस करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा ढांचे को और सुदृढ़ बनाना शामिल होना चाहिए। यह विस्फोट एक चेतावनी है कि आतंकवाद ने अपना रूप, साधन और संचालन का ढांचा बदल लिया है। इसलिए देश की सुरक्षा रणनीति भी अब पारंपरिक सीमाओं में बंधी नहीं रह सकती। भारत को ऐसी सुरक्षा नीति की जरूरत है जो न केवल वर्तमान खतरों को समाप्त करे बल्कि आने वाले समय में संभावित आतंकी हमलों को भी रोक सके। इस आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह भंडाफोड़ करना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना ही जनता के मन में यह विश्वास स्थापित करेगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। देश को यह दिखाना होगा कि आतंकवाद चाहे कितनी भी गहरी जड़ें जमाने कीकोशिश करे, भारत की संकल्प शक्ति उससे कहीं अधिक मजबूत है।सरकार और नेतृत्व की दृढ़ ईच्छा शक्ति आतंकवाद के नासूर को नेस्तनाबूद करने में कामयाब होगी।

स्कूली बच्चों ने बाल दिवस पर संभाली नमो भारत की कमान

गाजियाबाद/ नई दिल्ली। बाल दिवस के उपलक्ष्य में, एनसीआरटीसी ने एक विशेष आयोजन किया, जहाँ बच्चों ने एक दिन के लिए नमो भारत के संचालन की कमान संभाली। इस अनूठी पहल ने छात्रों को एक अनोखा मौका दिया कि वे नमो भारत की विभिन्न ऑपरेशनल भूमिकाएँ जैसे कि स्टेशन कंट्रोलर, टिकट वितरक, सिक्योरिटी इंचार्ज, एनाउंसरझकम-ट्रेन अटेंडेंट और स्टेशन मेंटिनेंस सहयोगी जैसी विभिन्न भूमिकाएं निभाएँ। इस पहल से बच्चों को भारत की प्रथम नमो भारत ट्रेन की संचालन प्रणाली और उससे जुड़ी विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त करने का एक मनोरंजक अवसर और ज्ञानवर्धक अनुभव प्राप्त हुआ।

एनसीआरटीसी स्टाफ के मार्गदर्शन में, बच्चों ने सीखा कि भारत की प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कैसे हर रोज हजारों यात्रियों के लिए एक तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करती है। उन्हें नमो भारत को निर्बाध रूप से संचालित करने वाली टीम और इसके लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों से भी परिचित कराया गया। छात्रों को इसमें बहुत जिज्ञासा थी, उन्होंने टीम से कई सवाल पूछे। इस अनोखी पहल में भाग लेने की खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ नजर आई। स्टेशन पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने छात्रों का स्वागत करते हुए उन्हें उन भूमिकाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जो उनके लिए तय की गई थी। छात्रों ने बेहद उत्साह, ऊर्जा और उत्सुकता से अपनी- अपनी भूमिका अदा की। इस दौरान कुछ छात्रों ने नमो भारत स्टेशन का प्रबंधन संभाला, अनाउंसमेंट की, सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, यात्रियों से बातचीत की और उन्हें टिकट वितरित किया। नमो भारत के यात्री अनाउंसमेंट में बच्चों की आवाज सुनकर और टिकट काउंटर पर बच्चों को टिकट वितरण करते देख आश्चर्यचकित हो गए। इस कार्यक्रम का छात्रों के साथ-साथ यात्रियों ने भी खूब आनंद लिया और एक दूसरे के साथ सेल्फी और तस्वीरें भी खिंचवाईं। कई यात्रियों ने बाल दिवस के इस खास दृश्य को अपने मोबाइल में कैद किया और एनसीआरटीसी की इस पहल की प्रशंसा की। छात्रों के साथ आए शिक्षकों ने एनसीआरटीसी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसने छात्रों को नमो भारत जैसी आधुनिक शहरी परिवहन के बारे में सीखने का महत्वपूर्ण और मनोरंजक अवसर प्रदान किया है। इन बच्चों की जिज्ञासा और खुशी देखकर टीम एनसीआरटीसी के अधिकारी और स्टाफ भी बेहद उत्साहित हुए। इसने एक तेज, सुरक्षित, आरामदायक और समावेशी परिवहन प्रणाली के निर्माण करने की टीम एनसीआरटीसी की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया और नमो भारत स्टेशनों को एक जीवंत सोशल और एजुकेशनल हब में परिवर्तित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इसके साथ ही, दिव्यांग छात्रों के एक समूह ने नमो भारत कॉरिडोर का दौरा भी किया। इन छात्रों ने नमो भारत ट्रेन से गाजियाबाद से आनंद विहार स्टेशन तक की यात्रा की और इस आधुनिक परिवहन प्रणाली की गति, समावेशिता और आराम का अनुभव किया। उन्होंने ट्रेन और स्टेशनों के समावेशी डिजाइन, आरामदायक सीट, दिव्यांगजनों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों और एनसीआरटीसी के सहयोगी स्टाफ के लिए उनकी सराहना की। एनसीआरटीसी समय-समय पर ऐसी पहलों के साथ दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों के समुदायों को सार्थक रूप से जोड़ने का निरंतर प्रयास करता रहता है। एक विश्वस्तरीय क्षेत्रीय रेल प्रणाली के निर्माण के साथ ही, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एनसीआरटीसी सभी वर्गों के लिए सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा वातावरण सुनिश्चित कर रहा है।

बालिकाओं को मिला आत्मरक्षा का संदेश

हापुड़। कस्बा धौलाना में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला उपनिरीक्षक रक्षा सिंह ने बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान उन्हें महिला सशक्तिकरण और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। उपनिरीक्षक रक्षा सिंह ने महिलाओं और बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1076 और डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अभियान में उनके साथ होमगार्ड रजनी भी मौजूद रहीं। थाना धौलाना प्रभारी मनीष चौहान ने बताया कि हापुड़ पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थाना धौलाना क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान 5.0 लगातार जारी है। इसके साथ ही, एंटी रोमियो अभियान के तहत संदिग्ध युवाओं से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आमजन से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और सहयोग करने का आह्वान कर रही है।

जल शक्ति अभियान में उत्कृष्ट सुधारों की ओर कार्य करें: अमित राज

गाजियाबाद। जनपद में जल संरक्षण, तालाब पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन तथा पर्यावरणीय परियोजनाओं के 12 नवम्बर से 14 नवम्बर तक तीन दिवसीय निरीक्षण के बाद शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित दुर्गावती सभागार में केंद्रीय नोडल अधिकारी एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशक अमित राज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में निरीक्षण के दौरान देखे गए विभिन्न स्थलों जैसे मोरटा, नायफल, नाहल, उखलारसी, अत्रौली एवं मसूरी झील के तालाब; विजयनगर की अफॉरेस्टेशन साइट; तथा ककड़ा, भोजपुर, मनोकामना सोसाइटी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दासना देहात में स्थापित रेनवॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई। निरीक्षण में कई स्थलों पर ड्रेन कनेक्टिविटी, डीसिल्टेशन, इंटरलॉकिंग लेवलिंग, सीवेज प्रवाह रोकथाम, जालियों की मरम्मत और ढलानों की स्थिरता से संबंधित सुधार आवश्यक पाए गए वहीं नाहल तालाब, मसूरी झील और विजयनगर मियावाकी वन को अत्यंत उत्कृष्ट और मॉडल स्थलों के रूप में सराहा गया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तालाबों की जलधारण क्षमता बढ़ाने, नियमित सफाई, डीसिल्टेशन और वर्षा जल संचयन इकाइयों के मेंटेनेंस को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या प्री-ट्रीटमेंट सिस्टम प्रस्तावित करने, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए ग्रीन कवर बढ़ाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बंधों पर उपयुक्त वनस्पति आवरण का अभाव है, जिसके कारण वर्षा के समय मिट्टी का कटाव होने की संभावना अधिक है। इसलिए बंधों की सुरक्षा एवं दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सभी ढलानों पर समयबद्ध रूप से घास लगाने का कार्य कराया जाए। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई तथा सभी विभागों को आगामी कार्यों हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

मंदिर जाओ सनातन अपनाओ की मुहिम की साथ दुलारी समिति ने बाल दिवस मनाया

साहिबाबाद। इंदिरा कॉलोनी के मंदिर परिसर में दुलारी सामाजिक सेवा समिति ने संस्कार, संस्कृति, सनातन अपनाओ की पाठशाला के साथ बाल दिवस हर्षोल्लास से मनाया। पिछले कई वर्षों से दुलारी सामाजिक सेवा समिति सामाजिक उत्थान कार्य , बाल विकास कार्य के माध्यम से समाज को एक अच्छा संदेश , अच्छी सोच देने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को बाल दिवस पर बच्चों को एक परिचर्चा के माध्यम से सनातन धर्म की जानकारी, अच्छे संस्कार और अपनी संस्कृति के बारे में अवगत कराया। उन्हें मंदिर जाने के लिए जागरूक किया गया। दुलारी सामाजिक सेवा समिति का यह कार्यक्रम मंदिर परिसर में ही आयोजित किया गया। हमे मंदिर जाना चाहिए।

मंदिर जाकर किस प्रकार पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। यह सब बातें बताई गई और उन्हें वहां पर स्थित भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करने का तरीका भी सिखाया। आमंत्रित अतिथि पंडित राहुल शर्मा समाजसेवी ने छोटे-छोटे बच्चों से जल अभिषेक के साथ पूजा पाठ भी करवाए गए और उनको पूजा विधि के साथ-साथ पूजा का महत्व भी बताया। दुलारी समिति की अध्यक्ष राधिका शर्मा ने बताया कि अतिथियों द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार और संस्कृति से रूबरू कराया गया। सनातन धर्म की जानकारी दी गई। बच्चों ने भी इसमें बढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों द्वारा कविता, भजन, देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई।

गाजियाबाद में बड़ा फेरबदल 11 थानों के प्रभारी बदले गए

गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार रात 11 थानों के प्रभारियों में बड़े स्तर पर बदलाव किया। इस कदम के तहत तीन थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया गया और अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए। ट्रोनिका सिटी थाने के एसओ सरवन कुमार गौतम और टीला मोड़ एसओ राजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं विजयनगर एसएचओ शशि चौधरी से चार्ज हटा लिया गया और उन्हें अब सीबीआईटी अपराध शाखा में भेजा गया है। बदलाव के बाद मोदीनगर थाने का प्रभारी निरीक्षक आनंद प्रकाश मिश्रा बनाया गया है। मोदीनगर में लगातार यातायात और व्यापारियों की शिकायतों के चलते इंस्पेक्टर नरेश शर्मा को खोड़ा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिहानीगेट थाने का प्रभारी निरीक्षक कुलदीप दीक्षित और कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक सचिन कुमार बनाए गए हैं। इंस्पेक्टर मनोज कुमार को कोतवाली से ट्रोनिका सिटी, धर्मपाल को पुलिस लाइन से विजय नगर, इंस्पेक्टर रवि बालियान को डायल 112 से टीला मोड़, तथा इंस्पेक्टर प्रशांत त्यागी को सीबीआईटी अपराध शाखा से डायल 112 में स्थानांतरित किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में करता था स्नैचिंग, मुठभेड़ में गिरफ्तार

गाजियाबाद। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह घटना कौशांबी थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोका था। आरोपी लंबे समय से लूट, स्नैचिंग और चोरी की वारदातों में शामिल था। पुलिस के अनुसार, 14 नवंबर को यूपी गेट के पास अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक काली स्कूटी तेज रफ्तार में आती दिखी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक स्कूटी मोड़कर नर्सरी के पीछे कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया।

कुछ दूरी पर स्कूटी गड्ढे में फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देखकर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, दो खोखे कारतूस, एक चोरी की स्कूटी और एक आईफोन बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान फैसल उर्फ फैजान उर्फ सलमान (26) के रूप में हुई है, जो दिल्ली के गौतमपुरी, न्यू उस्मानपुर में रह रहा था।

एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी फैसल ने गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर में लगातार लूट और स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। उसने 2 नवंबर को कौशांबी थाना क्षेत्र में भी मोबाइल लूट की वारदात की थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर गाजियाबाद और एनसीआर में लूट और स्नैचिंग से जुड़े दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पेंटिंग प्रतियोगिताओं में 1100 बच्चों ने दिखाई कला प्रतिभा

गाजियाबाद। कविनगर में रोटरी क्लब गाजियाबाद नॉर्थ ने रविवार को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें गाजियाबाद के 130 विद्यालयों के 1100 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर कला प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों ने अलग-अलग थीम पर अपनी कलाकारी दिखाई। वर्ष 2012-2013 में जन्मे बच्चों ने महाकुंभ 2014-2015 ने भारत के त्यौहार और 2026-2017 में जन्मे बच्चों को पिकनिक थीम पर पेंटिंग बनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुरादनगर अजीत पाल त्यागी ने गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में क्लब अध्यक्ष पुनीत अग्रवाल, सचिव रजत जिंदल, कोषाध्यक्ष शिशिर अग्रवाल तथा प्रोजेक्ट चेयरमैन ललित जायसवाल का योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन सुमेश गर्ग एवं सुधीर गुप्ता ने किया।

अब लेट नहीं होगी एंबुलेंस: छात्रों ने बनाया एआई मॉडल

ऑटोमैटिक डिटेक्ट होगा एक्सीडेंट और पहुंचेगी तत्काल मदद

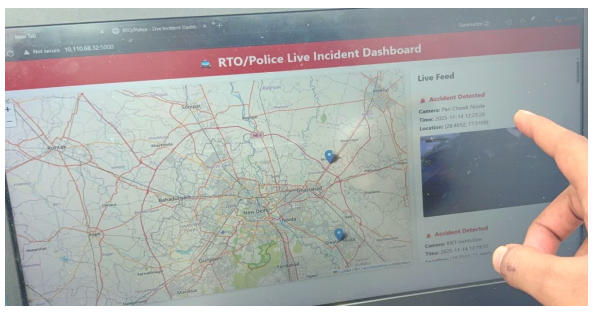

गाजियाबाद। भारत में सड़क हादसों का बढ़ता संकट चिंताजनक है। आए दिन सड़कों पर हुए हादसों की खबरें सुनते हैं। कई बार देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण जान चली जाती है। अब इस समस्या का समाधान बीटेक के छात्रों ने मिलकर निकाल लिया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने एक ऐसा एआई मॉडल विकसित किया है जो हादसे होने पर तुरंत पुलिस और नजदीकी अस्पताल को सूचित कर देगा।

छात्रों द्वारा विकसित किया गया एआई मॉडल सड़कों पर ट्रैफिक निगरानी के लिए लगे कैमरों का उपयोग करके सड़क हादसों का पता लगाएगा और तुरंत घटनास्थल के संबंध में तमाम जानकारी जैसे लोकेशन, फोटो आदि नजदीकी पुलिस स्टेशन और अस्पताल को भेजेगा। यह तकनीक एक्सीडेंट के समय घायलों तक एंबुलेंस पहुंचने की रिस्पांस टाइम को कम करेगी। करीब चार हफ्ते की मेहनत के बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र देवांग अग्रवाल, दिव्या नारायण वार्ष्णेय, कनिष्क पटेल, दिव्यांश माहेश्वरी और कुशाग्र वर्मा की टीम ने विकसित किया है। बीटेक के छात्र देवांग अग्रवाल के मुताबिक, कई बार देखा गया है कि एंबुलेंस को एक्सीडेंट की लोकेशन पर पहुंचने में वक्त लग जाता है। समय से एंबुलेंस के न पहुंचने पर घायल अस्पताल पहुंचने में लेट हो जाता है और कई बार घायल की मृत्यु हो जाती है। कई बार एक्सीडेंट होने के बाद आसपास किसी व्यक्ति की मौजूदगी ना होने के चलते पुलिस को सूचना नहीं पहुंच पाती है।

बीटेक के छात्र देवांग अग्रवाल ने बताया कि, हमने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया है जो सड़कों पर लगे कैमरा का इस्तेमाल कर एक्सीडेंट को डिटेक्ट करता है। यह वही कमरे होते हैं जो सड़कों पर चालान या ट्रैफिक निगरानी आदि के लिए लगाए गए होते हैं। एक्सीडेंट को डिटेक्ट करने के बाद तुरंत एक्सीडेंट से संबंधित फोटो और लोकेशन नजदीकी अस्पताल और पुलिस को भेजी जाती है। दिव्य नारायण वार्ष्णेय ने बताया, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कैमरे से मिले फीड को लाइव एनालाइज करता है। छात्र कनिष्क गौतम ने बताया योलोवी8 एआई मॉडल का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया है। योलोवी8 एआई मॉडल वीडियो के प्रत्येक फ्रेम में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। सड़कों पर वाहनों का लगातार आवागमन हो रहा है मॉडल के लिए सभी वाहन ऑब्जेक्ट है।

एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है कि कैसे एक्सीडेंट को डिटेक्ट करना है। एआई मॉडल को हजारों वीडियो फ्रेम रीड करवाए गए हैं। कोडिंग के माध्यम से एआई मॉडल को समझाया गया है कि दो ऑब्जेक्ट के टकराने, दो ऑब्जेक्ट के आपस ओवरलैप होने, अचानक से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होने या स्पीड में बड़ा बदलाव होने पर एक्सीडेंट होता है। इसी आधार पर एआई मॉडल बताता है कि एक्सीडेंट हुआ है। प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्रों का कहना है कि अगर इस मॉडल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और घायलों को समय पर चिकित्सीय मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। समय पर पुलिस और एंबुलेंस को घटनास्थल पर भेज कर बड़ी संख्या में सड़क हादसों में लोगों की जान बचाई जा सकती है।

कार खरीदने की चाहत में बना चोर, रैकी करते 2 लाख रूपए के साथ गिरफ्तार

गाजियाबाद। सिहानीगेट पुलिस ने एक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 लाख 20 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।

एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि यह मामला 3 नवंबर 2025 की रात का है, जब शांति एंटरप्राइज नामक दुकान से लगभग 12 लाख 80 हजार रुपये चोरी हो गए थे। दुकान मालिक ने सुबह ताला टूटा देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस और सर्विलांस टीम ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें एक युवक दुकान के पास घूमता नजर आया। 14 नवंबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि वही युवक इलाके में फिर दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने चोरी की पूरी वारदात स्वीकार कर ली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से एक गाड़ी खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त रकम नहीं थी। इसी वजह से उसने चोरी की योजना बनाई। उसने दुकान से 4 लाख 30 हजार रुपये चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि चोरी के बाद भी आरोपी सक्रिय था और आरडीसी के एक शोरूम की रेकी कर रहा था। वह वहां से भी चोरी करने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि आरोपी से बरामद 2 लाख 20 हजार रुपये फिलहाल कब्जे में ले लिए गए हैं। बाकी राशि उसने खर्च कर दी है। पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

संपादकीय

अन्तःकरण: सबसे बड़ी अदालत

2006 में बहुचर्चित निठारी की कोठी नंबर डी-5 में रहने वाले मोनिंदर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर बच्चों की बेरहमी से हत्या और अवशेष को घर के पीछे दफनाने का आरोप था। अब जब दोनों को कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद रिहाई मिल चुकी है, तो एक बार फिर उस दर्दनाक याद ने गांव में सन्नाटा फैला दिया है। उन घरों में जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब सिर्फ दर्द की परछाइयां बची हैं। 2005-2006 : नोएडा के निठारी गांव से कई बच्चे और महिलाएं लापता होने लगे। I-दिसंबर 2006 : पुलिस ने कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली के घर के पास से हड्डियां और शरीर के अंग बरामद किए। सुरेंद्र कोली को नौ सितंबर (रविवार) 2014 मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी। कोली को मेरठ जेल की एक हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। फांसी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। रविवार को अदालत बंद होने से अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने रात को ही सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा से मिलने का समय मांगा था। रात को करीब 11:45 बजे वरिष्ठ मुख्य न्यायमूर्ति एचएल दत्तू के घर विशेष अदालत लगी। रात में ही बहस हुई। कैलेंडर की तारीख बदल गई। उस समय रात को एक बजने से कुछ समय पहले ही विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में अदालत ने सुरेंद्र कोली के मामले में दोबारा सुनवाई के लिए इंदिरा जय सिंह को एक सप्ताह का समय देते हुए सुरेंद्र कोली की फांसी पर रोक लगा दी। सबसे पहले फोन करके मेरठ के डीएम और एसएसपी को इस फैसले की जानकारी दी गई। सुरेंद्र कोली की फांसी को अगले सप्ताह तक रोके जाने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें अदालत के आदेश की लिखित कापी मिलने तक इंतजार करने को कहा गया। निठारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद आदेश के अनुपालन में विशेष सीबीआई कोर्ट ने रिहाई परवाना जारी कर दिया। इसके बाद उसे गौतमबुद्धनगर के लुक्सर जेल से मुक्त कर दिया गया। निठारी कां हत्याकांड की तरह साक्ष्य के अभाव में अदालत के आदेश के बाद अपराधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है समाज में व्यक्तिगात शोषण के अतिरिक्त कुछ सामाजिक अत्याचार भी होते हैं-जातिवाद, बिरादरीबाद, प्रान्तवाद तथा कुटिल राजनीति इत्यादि के संकीर्ण दृष्टिकोण से। योग्य व्यक्ति के अधिकार छीन लिये जाते हैं और अयोग्य अथवा निम्नस्तरीय व्यक्ति को योग्य व्यक्ति के सिर पर बैठा दिया जाता है। इसके दो परिणाम संभव है-(1) व्यक्ति सिकुड़कर समाज के एक कोने में छिपकर पड़े हुए आत्मग्लानि की भट्टी में जलता रहे अथवा आत्महत्या आदि को अपनाकर अपमानजनक स्थिति का अन्त कर दे। (2) अथवा वह हिंसा का सहारा लेकर अपराधी के रुप में सामाजिक अपराध करना प्रारंभ कर दे। किंतु विवेकशील व्यक्ति ऐसे समय में भी सुदृढ़ रहकर अपने मन में अथवा व्यवहार में ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होने देता है। यह संकीर्णता की कदापि नहीं अपनाता है। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोयी जाती है। शुद्ध जल से ही कीचड़ को धो सकते हैं। जब आप पर अन्याय हो रहा है, तो दो ही राह हैं-घृणा को त्यागकर कर्त्तव्य ने नाते अत्याचार का प्रतिरोध करें तथा संघर्ष करें और जो भी फल हो उसे स्वीकार कर लें अथवा संतभाव को अपनाकर सब कुछ प्रभु पर छोड़ दें तथा अन्यायी के लिए भी सद्भावना ही करते रहें। नादिरशाही अन्याय का अन्त अवश्य होगा। एक छोटी-सी चींटी हाथी के लिए, एक छोटा-सा छिद्र विशाल नौका के लिए, एक नगण्य मनुष्य अत्याचारी के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। कमजोर पिट जाता है, किंतु सतानेवाला मिट जाता है। अत्याचारी अपने अत्याचार से स्वंय नष्ट हो जाता है। अत्याचारी के जीवन का अन्त सदैव भयानक होता है। सन्त क्षमादान कर प्रभु के दैवी न्याय पर सब कुछ छोड़ देता है। सन्त के लिए अपने व्यक्तिगत मामले में क्षमादान देना श्रेष्ठ होता है, किंतु यदि अन्य जन पर अन्याय हो रहा हो, तो उसका प्रतिरोध करना सदैव समुचित हैं।

इलेक्शन में जीत हार चलती रहती है

बिहार चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा खुश होने की जरुरत नहीं है सत्ता आती है जाती है इस संसार में एक दिन सबकुछ नस्ट होने वाला है लेकिन बिहार पर कितना कर्ज है उसे कैसे भरेंगे पैसे से वोट लेने की प्रथा जब चल पड़ी है तो बाद में पैसा खत्म होने पर वो फिर बदल जायेगा जहाँ तक चुनाव जीतने की बात है तो लोकसभा के बाद झारखण्ड में भी चुनाव हुए थे वहाँ हार मिली अतः जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है क्योंकि ऐ शरीर ही नश्वर है तो फिर भगवान राम सत्य है लोकसभा में जो सीटे मिली वो कहीं ना कहीं ऐ सबक दिया कि भगवान राम को राजनीती में मत घसीटे और बाद में जब ऐ मुद्दा को छोड़ कर विकास के कार्यों की ओर जनता के सामने नमन किया तभी जीत मिली भगवान राम की कृपा से ही मेरी सांस चल रही है जो आदि है ना अन्त है वही भगवान राम है जो मौत और जीवन से परे है वही भगवान राम है अतः इसपर राजनीति करना व्यर्थ है । जीत हार सत्ता विपक्ष जीवन में आते रहते हैं लोग चुनाव में हार जीत को लेकर आपस में व्यक्तिगत शत्रु हो जाते हैं और अंहकारी हो जाते हैं लेकिन एक समय के बाद ऐ खत्म होने लगता है, यश, पद, सत्ता, धन आदि के लिए लोगों के पीछे घूमने से आप आत्म-प्रतिष्ठा खो देंगे, तथा कुछ न मिलेगा और यदि मिला भी तो वह प्रतिष्ठा की कीमत चुकाने से दुःखद हो जायगा। प्रयत्न का अर्थ आत्म-पतन नहीं होना चाहिए।दृढ़ विश्वास रखो कि चरित्र का अपना ही एक महत्व है। चरित्र की दृढ़ता मन को सम्बल प्रदान करती है। आध्यात्मिकता मनुष्य को पलायन नहीं सिखाती है, बल्कि उसके अन्तर्जगत को सुव्यवस्थित कर उसे कर्म की ओर प्रवृत्त करती है तथा उसे समभावजनित स्थायी सुख एवं शान्ति प्रदान करती है। अध्यात्म एक विज्ञान है, एक कला है, एक दर्शन है। अध्यात्म मानव के जीवन में जीने की कला के मूल रहस्य को उद्घाटित करा देता है। आध्यात्मिक वातावरण मानों मन के जख्मों को धोकर, उन पर दिव्य मरहम लगाकर मानव को मानसिक स्वस्थता प्रदान करता है। ध्यान का दैनिक अभ्यास स्वास्थ्य एवं शांति के लिए निद्रा की भाँति परम आवश्यक है। थकने पर निद्रा कैसी सुखदा प्रतीत होती है। निद्रा आने पर मनुष्य श्रेष्ठ संगीत, भोग्य पदार्थ एवं भौतिक सत्ता को भी भूल जाता है। वे हेय हो जाते हैं। खोजना होता है तथा एक विशेष पद्धति अपनाकर अथक परिश्रम करना होता है। वे सब इच्छाएं और भय हमारे ही हैं, जो हमें अनजाने ही दुःखी रखते हैं। वे हमें भीड़ की भाँति घेरकर मानो पकड़ लेने का प्रयत्न करते हैं। धैर्य रखें तथा तटस्थ द्रष्टा ही रहकर अपने भीतर के गहरे स्तर को भी देखते ही रहें। वास्तव में अवचेतन मन भी गतिमान तो निरन्तर रहता है, किंतु हमें इसी अवस्था में ही उसका यह ज्ञान होता है । तब हमारे अवधान के समक्ष अवचेतन मन उद्घटित अथवा नग्न होकर दीखने लगता है। अवचेतन (अचेतन) के अतल गह्वरों में उतरने पर, समस्त संस्कारों, इच्छाओं, आशाओं, निराशाओं, स्मृतियों की परतों को उठाकर, अथवा उनका भेदन कर गहरे स्तर पर चेतना की निर्ग्रन्थ, निर्मल, अखण्ड सत्ता का संदर्शन एवं संस्पर्श हो जाता है। नित्यप्रति ऐसा अभ्यास करने पर ध्यान की पूर्वावस्था में धीरे-धीरे चेतन तथा अवचेतन मन प्रायः शान्त होने लगेंगे और उनकी चंचलता शिथिल अथवा न्यूनतम हो जायेगी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका गर्व भूलकर भी साधक को नहीं करना चाहिए। सत्य का अनुसंधता सदैव विनम्र रहता है। व्यक्तिगत हमला होने पर आपकी मान्यताओं एवं आस्थाओं की परीक्षा होती है। चरित्र ही आपकी सच्ची सत्ता है आपकी असली पहचान और शक्ति, आपकी प्रतिभा या धन-दौलत से कहीं ज्यादा आपके नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और व्यवहार से बनती है। चरित्र आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, सम्मान दिलाता है, और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है।

हमारा राज्य

मध्यप्रदेश में गाय के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान

मध्यप्रदेश अपनी अनेक विशेषताओं के लिये जाना जाता है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण यह प्रदेश देश भर में अपनी पृथक पहचान स्थापित कर चुका है। विभिन्न धर्म सम्प्रदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधकर रखने का अभिनव प्रयोग भी सिर्फ मध्यप्रदेश में ही हो रहा है। देश में मध्यप्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ गौशालाओं को सर्वाधिक अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस दिशा में आगे बढकर कई अहम फैसले लिये हैं। गौशालाओं की प्राथमिकता तय कर उनके अनुदान में लगातार बढ़ौत्तरी करने के साथ गाय के संरक्षण के लिये प्रशासनिक स्तर पर कड़े प्रावधान किये गए हैं। यहाँ बता दें कि डॉ मोहन यादव का नाता उस उज्जैन नगरी से है जो पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक वैभवशाली होने के साथ - साथ विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ महाकाल विराजते हैं। वेद - पुराणों में भी उज्जैन का धार्मिक महत्व कई गुना ज्यादा है। वहाँ रहकर वे गाय की सेवा, पूजा अर्चना करने के साथ उसे संरक्षण और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें गौ सेवा का भरपूर मौका मिला। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में गौ रक्षा को संकल्प के रूप में मानकर अब जागरूकता बढ़ी है। प्रदेश के लोग गाय की सेवा को सर्वोपरि तो मान ही रहे हैं साथ ही इसे धार्मिक दृष्टि से अपना अहम कर्तव्य मानकर उसकी रक्षा का दायित्व भी निभा रहे हैं। मध्यप्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर समय - समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा संस्कार में भी गाय के महत्व पर ज्यादा ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश में गाय के संरक्षण और उसके पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गौ संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रदेश में इस दिशा में वृहद कार्ययोजना चलाई जा रही है । यहां बता दें कि मध्यप्रदेश में लगभग दो हजार गौ शाला हैं। गौ शाला को गौसंवर्धन बोर्ड की निगरानी में सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ताकि कहीं किसी बात की दिक्कत न हो। पूर्व में अनुदान 20 रुपए प्रतिदिन प्रत्येक गाय के अनुसार निर्धारित था जिसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है । गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा निराश्रित गायों के लिए स्वावलम्बी गौशाला (कामधेनू निवास) योजना तथा कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

एक अनुमान के मुताबिक मध्यप्रदेश में तीन लाख गाय होने का अनुमान है । गौशाला की संख्या बढ ? के साथ गौ पालन के लिये लोग उत्साहित हैं। प्रसंगवश बता दें कि गौ वंश गांव आधारित अर्थव्यवस्था की धुरी है। ग्राम्य जीवन में गाय इतनी अधिक रच बस गयी है कि दोनों को अलग कर देख पाना कठिन हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि ह्यह्यभारत की सुख समृद्वि गाय और उसकी संतान के साथ जुड़ी है। इसी तरह अमेरिका के सुविख्यात डॉक्टर वर्कफील्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा ह्यह्यसच पूछो तो गाय समृद्धि और सम्पन्नता की जननी एवं माता है। प्राचीन काल में हिन्दू दूध, मक्खन का प्रचूर प्रयोग किया करते थे इसलिये वे शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ थे। उनके मस्तिष्क बहुत उवर्श थे। सहनशक्ति आश्चर्यजनक थी।ह्यह्व यहाँ बता दें कि गाय को प्राचीनकाल से ही सम्पदा का प्रतीक माना जाता रहा है। जिसके पास जितनी गाय रहती थीं उसे उतना ही धनवान माना जाता था।

अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस और भारत में छात्रों की वास्तविक स्थिति

विश्वभर में अंतरास्ट्रीय छात्र दिवस हम मनाते है। हर राज्य, शहर और गांवो में नजर डाले तो छात्रो की परिस्थितिया अलग अलग परिभाषित होती दिखाई देती है।अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस विश्वभर के विद्यार्थियों की संघर्षपूर्ण यात्रा, उनकी उपलब्धियों और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने का अवसर है। भारत जैसे विशाल और युवा देश में यह दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 40% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रणाली से जुड़ी है। परंतु देश के करोड़ों बच्चों का वास्तविक जीवन, उनकी पढ़ाईझलिखाई की परिस्थितियाँ, आर्थिक,सामाजिक चुनौतियाँ, पढ़ाई का बोझ, होमवर्क, और स्कूलों के कठोर नियम इन सभी को समझे बिना छात्र दिवस की प्रासंगिकता अधूरी रह जाती है। भारत में छात्र सिर्फ डेस्क और किताबों तक सीमित चरित्र नहीं हैं।वे संघर्ष, सपनों और दायित्वों से जूझती हुई नई पीढ़ी का प्रतिबिंब हैं। आज का विद्यार्थी जहां डिजिटल युग की तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं गरीबी, असमानता, फीस का बोझ, संसाधनों की कमी, मानसिक दबाव और भविष्य को लेकर असुरक्षा जैसे कई कारक उसकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं।

संघर्ष और संभावनाओं के बीच

भारत के विद्यार्थी एक विषम परिस्थिति में जीवन गुजारते हैं। एक तरफ दुनिया तेज गति से शिक्षण को तकनीकी से जोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर देश में अब भी हजारो बच्चे प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने से वंचित हैं। जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं, वे संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी, स्कूलों की असमान गुणवत्ता और आर्थिक संकट जैसी बाधाओं से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं।छात्र यथार्थ से दो प्रकार से जूझते हैं,जिसमे पहला शैक्षणिक दबाव और दूसरा सामाजिक और आर्थिक दबाव है।जो परिस्थितियों पर चोट करता है।इन दोनों के बीच संतुलन बनाना हर बच्चे के लिए आसान नहीं होता, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके लिए शिक्षा आज भी एक विलासिता जैसी लगती है। भारत में छात्रों को सबसे बड़ी जो कठिनाई झेलनी पड़ती है, वह है आर्थिक असमानता। करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो मुश्किल से अपने बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्च उठा पाते हैं।गरीबी के कारण शिक्षा पर प्रभाव पड़ता दिखाई देता है।लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं, पर वहाँ भी कई बार आवश्यक संसाधनों की कमी होती है।लेकिन फिर भी सरकार हर खर्च अपने स्तर पर कार्य को अंजाम दे रही है।मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों की कोचिंग, ट्यूशन और स्कूल फीस एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुकी है।ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी, परिवहन की कमी और कामकाज में बच्चों की मदद की मजबूरी पढ़ाई में बाधा डालती है।आज भी भारत के बहुत से बच्चे स्कूल के बाद किसी दुकान, ढाबे, खेत या छोटे-मोटे काम में माता-पिता का हाथ बंटाते हैं। यह आर्थिक बाध्यता बच्चों के अध्ययन समय को कम कर देती है और उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक असर डालती है। स्कूल शिक्षा में असमानता को दूर करना होगा।सरकार को देश मे समान शिक्षा लागू करने के लिए त्वरित निर्णय लेना होगा।

निजी बनाम सरकारी संस्थान

भारत का स्कूली ढांचा दो हिस्सों में विभाजित है। जिसमे निजी स्कूल में बेहतर सुविधाएँ है लेकिन अत्यधिक फीस के कारण बच्चे पढ़ नही सकते है। सरकारी स्कूल में सस्ती या मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है लेकिन कई जगह संसाधनों में कमी के कारण छात्र फायदा नही उठा पाते है।निजी स्कूल की चुनौतियाँ अत्यधिक है।अत्यधिक फीस हर महीने नई नई गतिविधियों का आर्थिक बोझ पड़ता है और यूनिफॉर्म, किताबें, परिवहन के भारी शुल्क से छात्र केमाता-पिता पर सामाजिक दबाव कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो। सरकारी स्कूलों की चुनौतियाँ भी अपार है। शिक्षकों की कमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, खेल-सुविधाओं और लाइब्रेरी की कमी और कई जगह शिक्षा की गुणवत्ता बहुत कमजोर होती दिखाई देती है।यह असमान व्यवस्था बच्चों के बीच असमानता को जन्म देती है। होमवर्क का बढ़ता बोझ

और तनाव मुश्किलें पैदा करता है। भारत में विद्यार्थियों पर होमवर्क का बोझ असाधारण रूप से अधिक है।अक्सर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को इतना अधिक होमवर्क दे दिया जाता है कि उनके खेलने और मानसिक विकास का समय छिन जाता है। होमवर्क के बोझ के प्रमुख कारण भी है।स्कूलों की प्रतिस्पर्धा, रैंकिंग का दबावऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के असाइनमेंट और परीक्षा आधारित मूल्यांकन यह बच्चों में तनाव, थकान, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई से दूरी पैदा कर देता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि छोटे बच्चों को कम से कम होमवर्क दिया जाना चाहिए ताकि वे सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले सकें । स्कूलों के कठोर नियम कायदे अनुशासन या मानसिक दबाव से छात्र की चिंता बढ़ जाती है।कई स्कूल बच्चों पर अत्यधिक अनुशासन और सख्त नियम लागू करते हैं।यह कोमल बाल के मष्तिष्क के लिए खतरनाक है।लंबे समय तक क्लास में लगातार टेस्ट, ड्रेस कोड की कड़ाई और नियम तोड़ने पर जुमार्ना,स्कूल बस, किताब या देर होने पर दंडसे बालक के मन मे नफरत पैदा हो जाती है।जहाँ अनुशासन आवश्यक है, वहीं अत्यधिक कठोरता बच्चों में भय और असुरक्षा पैदा करती है। शिक्षा का उद्देश्य सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना होना चाहिए, न कि दंड के माध्यम से दबाव बनाना।

मानसिक तनाव, अवसाद और प्रतिस्पर्धा का दंश भारत में छात्र मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं।परीक्षा में असफल होने का भय90% 95% अंक लाने की सामाजिक अपेक्षा,करियर को लेकर अनिश्चितता और माता-पिता का दबाव यह सब छात्रो को विपरीत दिशा की तरफ खिंचती है।सामाजिक तुलना में भीछात्र के मन मे एक प्रकार का दोष घर कर जाता है। कि फला के बच्चे ने इतना अच्छा किया, तुम क्यों नहीं ? कई तथ्यों के अनुसार छात्र आत्महत्या के मामलों में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। यह आंकड़ा बताता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों का मानसिक भार बढ़ा रही है। डिजिटल शिक्षा की दोहरी चुनौती भी है और अवसर भी, खतरा भी है।कोविड के बाद डिजिटल शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन डिजिटल खाई अभी भी व्यापक है।शहरों में टैब, मोबाइल, हाई-स्पीड इंटरनेट ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट व गांवों में नेटवर्क की कमी मोबाइल फोन का अभाव साझा उपकरणों पर निर्भरता के ये सभी कारण छात्र को विचलित करने का काम करते है। डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण और गरीब बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। छात्र की अन्य चुनौतियाँ भी है।

परिवहन, सुरक्षा, सामाजिक दबाव परिवहन समस्या

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है।स्कूलों तक आते-जाते समय छात्राओं की सुरक्षा कई क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है।कई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। खाली पेट स्कूल जाने से उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता। सामाजिक दबाव भी आज के परिपेक्ष्य में विरोधभास पैदा कर रही है।कई समुदायों में लड़कियों को उच्च शिक्षा की अनुमति नहीं मिलती, जिससे ड्रॉपआउट बढ़ता है।इन चुनौतियों को कम करने के लिए सरकारी प्रयास कर रहीं है।लेकिन नाकाफी है। भारत सरकार और राज्य सरकारें छात्रों की समस्याओं को कम करने के लिए कई कदम उठा रही हैं। नई शिक्षा नीति में रटने की बजाय कौशल आधारित शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करना ही छात्रो की मूल समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। बच्चों को पसंद के विषय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। डिजिटल शिक्षा का विस्तार, मध्याह्न भोजन ,गरीब बच्चों में कुपोषण कम करने से बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ी है।

प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उपलब्ध होने से छात्र को मदद मिलती है।आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहारा कन्या छात्रवृत्ति योजनाएँ। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन जैसे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सामग्री उपलब्धब है। सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है।यह कार्य निजी स्कूल वाले बहुत करते है। स्मार्ट क्लास पुस्तकालय ,खेल मैदान आदि की पूर्ति स्कूल विभाग वालो के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। होमवर्क कम करने की नीति अपनानी होगी।कई राज्यों ने प्राथमिक कक्षाओं में होमवर्क पूरी तरह बंद किया है।

नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। बच्चों की मानसिक समस्याएँ कम करने का प्रयास समय की मांग है।भारत में छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निम्न कदम आवश्यक है। होमवर्क का बोझ कम किया जाए,खेलने कूदने और रचनात्मक गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाए। सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों के बराबर मजबूत बनाया जाए। डिजिटल संसाधनों की बराबरी सभी तक उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करानी होगी।मुफ्त यूनिफॉर्म,मुफ्त किताबें, परिवहन सुविधा दी जाय।मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए और परीक्षा प्रणाली में सुधार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।रटने की जगह समझ पर आधारित मूल्यांकन होना जरूरी है।शिक्षकों का प्रशिक्षण और अधिक प्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षक ही बच्चों की दिशा बदल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत का छात्र वास्तव में स्वतंत्र है ?क्या उसे मनचाहा सीखने का अधिकार है ?

क्या वह आर्थिक और सामाजिक दबावों से मुक्त है ?

नोएडा पुलिस ने नाले से मिली अज्ञात महिला की लाश की गुत्थी सुलझाई, हत्यारोपी गिरफ्तार

आरोपी बोला-ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर किया कत्ल, 'बस में काटे थे गर्दन-हाथ'

नोएडा। नोएडा के थाना सेक्टर-39 पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही से घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि बीते 6 नवम्बर थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस को सूचना मिली थी कि नाले में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला है। सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और शव की पहचान और मामले के खुलासे के लिए लगभग 9 टीमें गठित की गई। इस दौरान 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की गई और लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया। सामने आया कि 5 नवम्बर को एक बस लाइट बंद कर घटनास्थल की तरफ जा रही थी, जिसकी जानकारी निकालने पर पता चला कि बस को मोनू सिंह चलाता है, जो बरौला में रहता है। जांच में पता चला कि एक महिला 5-6 दिन से लापता है, जिसका मोनू सिंह से विवाद चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से मोनू सोलंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार व अन्य सामान बरामद किया गया। डीसीपी ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ के बाद बताया कि महिला और उसकी मां जींस की फैक्ट्री में काम करते थे, जिस कारण दोनों की जान-पहचान हो गई। इसके बाद महिला उसके कमाए सारे पैसे ले लिया करती थी। इस बीच हमारी लड़ाई भी हुई, जिसके बाद महिला ब्लैकमेल करने लगी। आरोपी ने कहा कि मेरी दो बेटी व एक बेटा है। महिला धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी बेटी से अनैतिक काम करवाउंगी। इसी कारण महिला की हत्या की योजना बनाई। उसने आगे बताया, 5 नवम्बर को मैं महिला के घर गया और उसे अपनी बस में बैठा ले आया। इसके बाद रास्ते में पराठा लिया और साथ में खाने लगे। इस दौरान महिला ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और हमारी लड़ाई हो गई। इसपर मैंने धारदार हथियार से गर्दन काट दी और पहचान न हो इसलिए हाथ भी काट दिए और शव को नाले में फेंक दिया। वहीं हथियार व अवेशष गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार के पास सूखे नाले में फेंक दिया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।

बुलंदशहर में दो सगी बहनों को बेच दिया पुलिस ने पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बुलंदशहर की मूल निवासी दो सगी बहनों को बेचने के आरोप में पिताझपुत्र की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर के थाना देहात कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से दो सगी बहनों को बहला-फुसलाकर आरोपी पिता सुनील और उसका बेटा सोनू अपने साथ ले गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने युवतियों का अपहरण कर उन्हें 1 लाख 60 हजार रुपए में बेच दिया था। पैसों के बदले छोटी बहन की जबरन शादी भी करा दी गई थी। मामले में परिजनों ने केस दर्ज कराया था। युवतियों के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया। सर्विलांस सेल की तकनीकी मदद से पुलिस ने दोनों बहनों का लोकेशन ट्रेस किया। दोनों युवतियों को सुरक्षित बरामद करने में सफलता हासिल की। साथ ही, आरोपी सुनील और सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एएसपी ऋजुल ने बताया कि दोनों आरोपी थाना भटनी जनपद देवरिया निवासी हैं। वे मजदूरी करने के लिए ग्रेटर नोएडा की निजी कंपनी में काम कर रहे थे। लंबे समय से पैसों के लालच में युवतियों को बहला फुसलाकर बेचने जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। फिलहाल पुलिस एसपी ऋजुल पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस टीम की ओर से यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल तो नहीं हैं। थाना देहात कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दो मासूम युवतियों की जिंदगी बच सकी है।

नोएडा में धड़ाधड़ कट रहे चालान

10 हजार से ज्यादा गाड़ियों पर हुआ एक्शन; 36 वाहन जब्त

नोएडा। नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। यातायात माह में गौतमबुद्ध नगर पुलिस के जागरूक करने पर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तीन सवारी और नंबर प्लेट पर जातिसूचक लगाकर फरार्टा भरने वाले लोगों को पुलिस ने शनिवार को आड़े हाथों लिया। ऐसे लापरवाह लोगों के 36 वाहनों को सीज किया। दस हजार से ज्यादा वाहनों के चालान किए। उधर, पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। यातायात माह में पुलिस लोगों को नियमों का पाठ भी पढ़ा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी के साथ-साथ चालान करने व वाहन सीज करने की सख्त कार्रवाई भी कर रही है। डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि टीम ने अभियान चलाकर शनिवार को मैनुअल तरीके से 4,838 चालान, जबकि आइएसटीएमएस कैमरों से 5,567 वाहनों के चालान किए। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 36 वाहनों के खिलाफ सीज की कार्रवाई की। इनमें बिना हेलमेट वाले 4,893, तीन सवारी बैठाकर चलने वाले 356, ड्रिंक ड्राइव के 15 व एनजीटी का उल्लंघन करने वाले 490 शामिल रहे। उधर, यातायात निरीक्षक प्रवीन कुमार ने बताया कि सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन, मोरना बस डिपो, निठारी मार्ग, सेक्टर 29 मार्ग पर प्रचार प्रसार वाहन को खड़ा किया गया। इस पर लगी एलइडी के माध्यम से लोगों को यातायात नियम, संकेत, गोल्डन आवर्स, राहवीर योजना के बारे में जानकारी दी गई। सेक्टर 108 स्थित पुलिस आयुक्त सभागार में टीम ने लोगों को सीपीआर के बारे में जागरूक किया और प्रशिक्षण भी दिया।

बुलंदशहर की डेयरी में हो रही थी दूध की हाईटेक चोरी, तीन गिरफ्तार

■ एक बार में लग रही थी साढ़े तीन लाख की चपत

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे-91 स्थित क्रीमी फूड्स के मिल्क प्लांट्स से 2.25 करोड़ की हाईटेक दूध चोरी का मामला सामने आया है। दूध की चोरी मिल्क टैंकर्स में दूध के वजन में गड़बड़ी करके की जाती थी। कम्पनी के दूध की चोरी के आरोप में खुर्जा देहात पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। खुर्जा कोतवाली देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे-91 पर क्रीमी फूड्स का मिल्क प्लांट हैं। यहां दूध उत्पादों की अलग-अलग पैकेजिंग और उत्पादन किया जाता है। स्याना अड्डा स्थित ज्योति डेयरी के मालिक ओम प्रकाश सिंह उर्फ खचेडू, उनका बेटा महेन्द्र सिंह ट्रक ड्राइवर भूपेंद्र सिंह और मधुसूदन कम्पनी के धर्म कांटे के ऑपरेटर प्रेम कुमार गौतम के साथ मिलकर टैंकर में 5 से 7 हजार लीटर दूध का वजन बढाकर कम्पनी में सप्लाई देते थे। एक बार में ये लोग तीन लाख से साढ़े तीन लाख रुपये का दूध चोरी कर कम्पनी को मोटी चपत लगाते थे। यह सिलसिला लम्बे समय से चल रहा था। जिस समय धर्मकांटे पर दूध के कैंटर की तौल में गड़बड़ी की जा रही थी, उस समय कम्पनी के कर्मचारी ने मौके पर प्रेम कुमार गौतम और ड्राइवर भूपेंद्र को पकड़ लिया। कर्मचारी ने इसकी शिकायत मैनेजमेंट से की। कम्पनी की ओर से खुर्जा देहात थाने मे त्रक्ष्फ़दर्ज करवाई गई। इस मामले की शिकायत कम्पनी प्रबन्धन ने सीएम योगी से भी की थी । उक्क्ष्कलानिधि नैथानी के निर्देश पर एसएसपी बुलंदशहर मामले की जांच सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह से करवाई। सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह ने बताया ज्योति डेयरी के मालिक ओम प्रकाश सिंह उर्फ खचेडू और महेन्द्र सिंह एवं टैंकर ड्राइवर भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बयानों में आरोपियों ने दूध चोरी करना भी कबूल किया है।

चार दिन में उखड़ी सड़क, कई जगह डामर गायब; ठेकेदार कर रहा मनमानी

नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-3 के सी ब्लॉक की सड़क के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। निवासियों का आरोप है कि हाथ से ही सड़क की डामर निकल रही है। साथ ही कुछ जगह ऐसी है, जहां डामर ही नहीं डाली गई। वहां पुरानी सड़क दिख रही है। वहीं ब्लॉक की सड़कों पर डाली गई डामर की बजरी निकल रही है। आरोप है कि ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर रहा है और प्राधिकरण के अफसर उसे अनदेखा कर रहे हैं। निवासियों ने प्राधिकरण से शिकायत कर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

नोएडा में पाबंदियों के बाद दो हजार से ज्यादा कामगार कर रहे थे निर्माण कार्य, दो करोड़ का जुर्माना लगाया

जेपी विशटाउन की परियोजनाओं में तीन भूखंडों पर 90 हजार का जुर्माना

नोएडा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर शहर में ग्रेप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत निर्माण और तोड़फोड के कार्यों पर रोक है। जेपी विशटाउन की अलग-अलग परियोजनाओं में दिन रात चल रहे कार्य को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। दो हजार से अधिक कामगार यहां कार्य करते हुए मिले। नियमों के उल्लंघन को लेकर दो करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। बता दें जेपी विशटाउन में अधूरी परियोजनाओं को सुरक्षा रियल्टी पूरा कर रही है। निवासियों की ओर से यहां पर निर्माण कार्य के दौरान हो रहे नियमों के उल्लंघन की पूर्व में कई शिकायतें दी। ग्रेप-3 की पाबंदियों के बाद भी यहां निर्माण कार्य चल रहा था। शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला और तहसील प्रशासन समेत यूपीपीसीबी (उत्तर प्रदेश पलूशन कंट्रोल बोर्ड) की टीम निर्माणाधीन साइट पर पहुंची। यहां पर दो हजार से अधिक कामगार कार्य करते हुए मिले। अलग-अलग परियोजनाओं में यह कामगार कार्य कर रहे थे। मौके पर पूछताछ की गई। निर्माण साइट पर धूल जमा थी और मिट्टी उड़ रही थी। बढ़ते प्रदूषण के स्तर से लोगों को परेशानी हो रही थी। टीम ने सेक्टर-128, 131, 133 समेत 134 में विशटाउन की परियोजनाओं पर 50-50 लाख रुपये समेत दो करोड़ रुपये का जुमार्ना किया है। इसके साथ ही पाबंदियों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। जेपी इंफ्राटेक के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रेप के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

जेपी विशटाउन की परियोजनाओं में निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को लेकर बृहस्पतिवार को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया था। इसके बाद भी यहां निर्माण कार्यों के दौरान नियमों का उल्लंघन मिला। प्रदूषण बोर्ड की टीम ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-19 के ब्लाक ए स्थित भूखंड संख्या पांच, 768, 770 पर कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना किया है। यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और नियमों का पालन नहीं पाया गया।

बुलंदशहर में स्याना पुलिस ने पांच वारंटी किए गिरफ्तार

बुलंदशहर। स्याना कोतवाली पुलिस ने विभिन्न स्थानों से पांच वारंटियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए की गई है। कोतवाली प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकी प्रभारी आकाश सोलंकी, अजय कुमार और हल्का इंचार्ज अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इन वारंटियों को पकड़ा। सभी गिरफ्तार वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए वारंटियों में हरवानपुर, थाना स्याना, जिला बुलंदशहर निवासी शिवा पुत्र चंद्रवीर और चंद्रवीर पुत्र गोधा सिंह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बरौली वासुदेवपुर, थाना स्याना निवासी राहुल पुत्र संतोष; नयाबांस, थाना स्याना निवासी अनिल कुमार पुत्र सुरेंद्र; और चांदपुर पूठी, थाना स्याना निवासी सुरेंद्र पुत्र धर्म सिंह को भी पकड़ा गया है।

मधुमेह को दवा से ही नहीं, संतुलित जीवन से परास्त करें

दुनिया में बढ़ती मधुमेह की भयावहता इसलिये चिन्ताजनक है कि हर तीसरा शहरी वयस्क डायबिटीज से जूझ रहा है। यह बीमारी अनेक अन्य बीमारियों को भी बढ़ाने का बड़ा कारण है। मधुमेह के बढ़ने के कारणों में मुख्यतः खानपान में अनियमितता और शारीरिक निष्क्रियता सबसे बड़ी वजह है। विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज कर दुनिया को मधुमेह से राहत देने का मार्ग दिखाया। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1991 में इसकी शुरूआत की थी। इस वर्ष का थीम है मधुमेह और समग्र कल्याण। यह थीम इस तथ्य पर केंद्रित है कि मधुमेह का उपचार केवल दवाइयों से नहीं बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली से संभव है। मधुमेह आज एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। बदलती जीवनशैली, अनियमित भोजन, तनाव, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता इसके प्रमुख कारण हैं। यह बीमारी चुपचाप शरीर को भीतर से खोखला करती है और हृदय, गुर्दे, आंखों और नसों पर गहरा असर डालती है। मधुमेह को नियंत्रित करना केवल चिकित्सा का विषय नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। इसके लिए सबसे पहले जीवन में संतुलन एवं सात्विक जीवनशैली की आवश्यकता होती है यानी संतुलित आहार, संतुलित नींद, संतुलित विचार और संतुलित आचरण। जीवन का यह संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। जब हम अपने जीवन को एक अनुशासन में ढालते हैं, तो रोग अपने आप दूर भागते हैं। मधुमेह आज केवल रोग नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है।

मधुमेह का प्रबंधन केवल दवा और आहार तक ही सीमित नहीं है; इसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता, तनाव प्रबंधन, जीवनशैली शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल है। इसका लक्ष्य रोगी को मधुमेह की चुनौतियों का सामना करते हुए एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। समग्र देखभाल, शीघ्र हस्तक्षेप और सहायक वातावरण को बढ़ावा देकर, मधुमेह रोग के बजाय व्यक्ति के उपचार के महत्व पर जोर देना मधुमेह दिवस का उद्देश्य है। यह दिवस मधुमेह से पीड़ित लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का अभियान डॉक्टरों, नीति निमार्ताओं और समुदायों से आग्रह करता है कि वे केवल रक्त शर्करा के स्तर से आगे बढ़कर रोगी के संपूर्ण कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें।

डायबिटीज जैसी घातक एवं असाध्य बीमारी को नियंत्रित करने के लिये अफवाहों से बचना जरूरी है, इसके लिये बड़ा दिल नहीं, समझदार दिल होना चाहिए। मर्यादित आहार ही, इस बीमारी को रोकने का एक सस्ता और असरदार उपाय हो सकता है। डायबिटीज (मधुमेह) की समस्या भारत समेत पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज पहले अमूमन अधेड़ उम्र के लोगों में होती थी, अब यह बच्चों एवं युवकों को भी शिकंजे में ले रही है। भारत में करीब 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। वहीं विश्व में 44 करोड़ लोग इससे पीड़ित है। भारत में डायबिटीज की प्रचलित दर 11.5 प्रतिशत है, जबकि प्री डायबिटीज के मामलों की दर 15.3 प्रतिशत तक पहुँच गई है , यानी देश का हर 10 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित है। एक अनुमान के अनुसार 85 करोड़ लोग दुनिया भर में डायबिटीज के मरीज 2050 तक हो जाएंगे। मधुमेह से बचने और इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नियमित शारीरिक गतिविधि। सुबह-सुबह की सैर, हल्का व्यायाम, दौड़ना या साइकिल चलाना न केवल शरीर को सक्रिय रखता है बल्कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी संतुलित करता है। इसके साथ ही योग और ध्यान का अभ्यास मधुमेह के नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी माना गया है। योग केवल शरीर को लचीला नहीं बनाता बल्कि मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है। प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे योग अभ्यास इंसुलिन के स्राव को संतुलित करते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं। ध्यान से मन की अस्थिरता और चंचलता कम होती है, जिससे तनाव नियंत्रित रहता है। तनाव और अवसाद मधुमेह के छिपे हुए शत्रु हैं। जब मन तनावग्रस्त होता है तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाते हैं। इसलिए मन को शांत और प्रसन्न रखना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को स्वस्थ रखना। मधुमेह के प्रबंधन में भोजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खानपान में शुद्धता और संयम दोनों ही जरूरी हैं। आज के समय में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, तले-भुने और मीठे खाद्य पदार्थों की भरमार ने लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया है। भोजन में सादा, ताजा और पौष्टिक आहार अपनाना ही सबसे बड़ी दवा है। साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, सलाद, फल, अंकुरित अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी-ये सब मिलकर शरीर को ऊर्जा तो देते ही हैं, मधुमेह को भी नियंत्रित रखते हैं। अधिक तला-भुना, मिठाई, नमक, और चाय-कॉफी जैसी चीजें सीमित मात्रा में लेनी चाहिए। समय पर भोजन करना और ओवरईटिंग से बचना भी आवश्यक है। खाना न केवल पेट भरने का माध्यम है बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। ह्यजैसा अन्न वैसा मनह्न-यह कहावत मधुमेह के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। संतुलित जीवनशैली का अर्थ केवल आहार-विहार का नियंत्रण नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या भी है। जो व्यक्ति अपने दिन का एक निश्चित समय योग, ध्यान और आत्मचिंतन में लगाता है, वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, असंतोष जैसी भावनाएं मन में रासायनिक असंतुलन पैदा करती हैं जो धीरे-धीरे शरीर में रोगों का कारण बनती हैं। अति-विचार से बचना भी जरूरी है। मधुमेह से बचने के लिए इन मानसिक विषों को दूर रखना उतना ही आवश्यक है जितना दवा लेना। अपने मन को हल्का और हृदय को प्रसन्न रखने की कला सीखनी होगी। धार्मिक प्रवृत्तियाँ, सत्संग, संगीत, साहित्य, प्रकृति के निकट समय बिताना, परिवार के साथ हंसी-मजाक करना-ये सब जीवन को संतुलन और आनंद से भर देते हैं। मधुमेह के रोगियों को नियमित रूप से अपने शुगर स्तर की जांच करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। दवा के साथ-साथ आत्म-निगरानी और जीवनशैली में निरंतर सुधार ही स्थायी स्वास्थ्य का आधार है। छोटी-छोटी बातों में सावधानी बड़ी बीमारियों से रक्षा करती है। शरीर को सक्रिय रखना, मन को शांत रखना और भोजन को संयमित रखना-ये तीन सूत्र मधुमेह नियंत्रण के त्रिदेव हैं। इस वर्ष के विश्व मधुमेह दिवस का संदेश यही है कि केवल दवा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलनी होगी। मधुमेह को नियंत्रण में रखने का सबसे कारगर उपाय है-ह्लसंतुलित जीवन।ह्व जब मन, शरीर और आत्मा का समन्वय होता है तो स्वास्थ्य अपने आप खिल उठता है। इस 14 नवम्बर को हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी जीवनशैली को अनुशासित, सकारात्मक और स्वास्थ्य-केंद्रित बनाएंगे। नियमित योग और ध्यान करेंगे, भोजन में संयम रखेंगे, तनाव को दूर करेंगे और अपने शरीर को प्रेम से समझेंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मधुमेह जैसी बीमारी हमें भयभीत करने के लिए नहीं आई, बल्कि हमें सजग, अनुशासित और संतुलित जीवन जीने का संदेश देने के लिए आई है। अगर हम यह संदेश समझ जाएं तो मधुमेह भी जीवन के संतुलन की शिक्षक बन जाती है।

जनतंत्र लाइव
(दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक)
मेरठ-बागपत
Email: jantantralive@gmail.com
सोमवार, 17 नवम्बर 2025 से रविवार 23 नवम्बर 2025, नई दिल्ली

शिकायतों का सही निस्तारण न करने वालों जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी

बागपत। जिले की तीनों तहसीलों में शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।जिलाधिकारी अस्मिता लाल व पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बागपत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जनसामान्य की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बागपत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में 47 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से मौके पर 11 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बड़ौत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जन सामान्य 36 शिकायतें प्राप्त हुई मौके पर 4 का निस्तारण किया गया और संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। खेकड़ा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जन सामान्य की 8 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से मौके पर 2 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में कोई भी प्रार्थना पत्र उसका 7 दिन के अंदर निस्तारण कर दिया जाए, कोई प्रकरण संवेदनशील है तो उसकी समय अवधि 7 दिन और बढ़ाई जा सकती है। सभी प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण होगा सही निस्तारण न करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले आज बागपत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सरल और सम लाभ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कैंप लगाया गया जिसमें पेंशन दिव्यांग राशन कार्ड आदि संबंधित विभाग को स्टाल लगाए गए, तहसील दिवस के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर एसडीएम बागपत अमरचंद वर्मा ,नायब तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी अंशु जैन सहित आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे का काम अंतिम चरण में चल रहा

बढ़ेगा शहर का रिंग रोड, लोगों को मिलेगा लाभ

मेरठ। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस-वे तेजी से अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में इस एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसी के साथ प्रयागराज में रिंग रोड के विस्तार की भी तैयारियाँ तेज हो गई हैं। शहर की परिवहन संरचना को और मजबूत करने के लिए रिंग रोड अब पाँच से छह किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले रिंग रोड को 65 किमी तक विकसित करने की योजना बनाई थी। लेकिन बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब यह लंबाई 71 किमी तय की गई है। पहला चरण 31 किलोमीटर में पहले से निमार्णाधीन है, जबकि दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। रिंग रोड का दूसरा चरण यमुनापार से शुरू होकर गंगापार के सोरांव तहसील के दांदूपुर इलाके तक पहुंचेगा। इस हिस्से की कुल लंबाई लगभग 40 किमी होगी। खास बात यह है कि इस फेज में गंगा और यमुना पर दो सिक्स-लेन पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिनकी संयुक्त दूरी करीब आठ किलोमीटर होगी। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, रिंग रोड के विस्तार का उद्देश्य बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकना है। नई कनेक्टिविटी से वाहन शहर की सीमा पर ही रिंग रोड पकड़ सकेंगे और बिना शहर की भीड़ में घुसे अपनी यात्रा आसानी से पूरी कर पाएंगे। सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज की लागत 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये के बीच अनुमानित है। इसके लिए एलाइनमेंट का काम तेज गति से चल रहा है। जैसे ही मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी, रिंग रोड के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

प्रेम प्रसंग के विरोध पर पत्नी की हत्या, पति सहित पांच गिरफ्तार

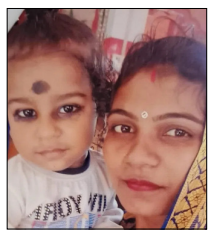

मेरठ। छह महीने से लापता चल रही इंदिरापुरम कालोनी निवासी रीता (26) की हत्या कर शव गंगनहर में फेंका गया था। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए परतापुर थाना पुलिस ने पति सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पुलिस ने हत्यारोपी पति हरिनंदन, सास रामपरी, ससुर शंभुशरण, देवर दिपांशु और कार चालक प्रवेश शामिल हैं। जांच में सामने आया कि पति के प्रेम-प्रसंग का विरोध करने पर रीता की हत्या की गई। उसके लापता होने की कहानी बनाकर पति मुंबई में अपने दोस्त के पास जाकर छिप गया था। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि मूलरूप से बिहार के दरभंगा जिले के सिहोल थाना क्षेत्र के विरोज गांव निवासी हरिनंदन यादव पत्नी रीता के अलावा तीन वर्षीय बेटी आयुषी के साथ परतापुर की इंदिरापुरम कॉलोनी में रह रहा था। वह परतापुर की एक कंपनी में काम करता था। इसी वर्ष 24 मई को रीता के पिता गणेश ने परतापुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सर्विलांस के माध्यम से हरिनंदन का फोन मुंबई में ट्रेस किया गया। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ के अनुसार पूछताछ में हरिनंदन ने बताया कि उसका एक महिला से प्रेम-प्रसंग हो गया था। इसकी जानकारी रीता को लगी तो वह लड़ाई करने लगी।

खेकड़ा तहसील में लेखपालों ने किया धरना प्रदर्शन: समस्याओं के समाधान की मांग उठाई

बागपत। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर शनिवार को खेकड़ा तहसील में लेखपालों ने धरना प्रदर्शन किया। खेकड़ा, बागपत स्थित तहसील परिसर में बड़ी संख्या में लेखपाल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। उन्होंने विभागीय उपेक्षा पर नाराजगी जताई।

लेखपालों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन पदाधिकारियों ने अपनी आवाज उठाई, उनका शासनादेशों के विपरीत स्थानांतरण कर दिया गया, जिसे उन्होंने संगठन के प्रति अनुचित कार्रवाई बताया। लेखपालों के अनुसार, प्रदेशभर में लेखपालों की संख्या बेहद कम है। विभागीय कार्यों के साथ-साथ गैर-विभागीय कार्यों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। संसाधनों की कमी के कारण कार्य निष्पादन में दिक्कतें आती हैं। उन्होंने अधिकारियों पर

आरोप लगाया कि वे समस्याओं को समझने के बजाय अत्यधिक दबाव बनाकर काम करवाने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं।धरने में शामिल लेखपालों ने बताया कि पिछले छह वर्षों में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने कोई आंदोलन नहीं किया। उन्होंने अनुशासित तरीके से अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को भी सफल बनाया है। इसके बावजूद, विभागीय संवर्ग और संगठन की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में परिषद और शासन स्तर पर उनकी मांगों पर सहमति बनी थी। कई संस्तुतियाँ भी की गई थीं, लेकिन पिछले छह वर्षों में इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपालों के अनुसार, न तो कोई समाधान मिला और न ही शासन-परिषद स्तर पर गंभीरता दिखाई गई। लेखपालों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए विशेष रूप से ₹संपूर्ण समाधान दिवस₹ के दिन ही धरना दिया। उनका उद्देश्य था कि उनकी समस्याएँ प्रशासन के सामने मजबूती से रखी जा सकें। लेखपाल प्रवीण कुमार और अन्य लेखपालों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहींकी गई तो वे कार्य बहिष्कार करेंगे और, मंत्री, विधायक, संसद के आवास पर प्रदर्शन व विधान सभा पर प्रदर्शन करेंगे।

मेरठ में अवैध मिनी कमेले पर छापा

मेरठ। मेरठ में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की टीम ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के पिल्लोखड़ी पुल के पास एक अवैध मिनी कमेले पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान एक दर्जन कटे हुए पशु बरामद किए गए और गोदाम मालिक समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त छापेमारी में बरामदगी यह पूरी कार्रवाई गुप्त रूप से की गई, जिसकी सूचना लिसाड़ी गेट पुलिस को नहीं दी गई थी। एसपी सिटी की टीम ने कोतवाली और देहली गेट थानों के बल के साथ मिलकर इस छापेमारी को अंजाम दिया। मौके से भारी मात्रा में मांस भी जब्त किया गया। गोदाम और आरोपी ऊंचा सद्दीकनगर निवासी शोएब अबू बकर मस्जिद के निकट एक गोदाम में यह अवैध मिनी कमेला संचालित किया जा रहा था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थीं। आरोपियों पर लंबे समय से अवैध कटान और पशु हनन करने का आरोप है। पुलिस की आगे की कार्रवाई पुलिस ने मौके से कई संदिग्ध वस्तुएं भी जब्त की हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

रालोद कार्यकर्ता विशु तोमर की हत्या से पल्ला झाड़ रही गाजियाबाद पुलिस

बागपत। बामनौली गांव के रालोद कार्यकर्ता विशु तोमर की हत्या में गाजियाबाद पुलिस पल्ला झाड़ती नजर आ रही है और बागपत पुलिस के पाले में गेंद फेंकी जा रही है। इसको लेकर परिवार वालों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, जो लगातार पुलिस अफसरों से हत्याकांड का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। बामनौली गांव निवासी विशु तोमर तीन नवंबर को फोन आने पर घर से चले गए। उन्होंने फोन पर परिजनों को अगले दिन वापस आने के बारे में बताया। इसके बाद विशु का फोन बंद हो गया और वह वापस भी नहीं लौटे। सात नवंबर को चाचा नरेश तोमर ने विशु की गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में पता चला कि चार नवंबर को गाजियाबाद जिले के खन्नानगर में विशु का शव मिला और पुलिस ने लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो विक्रांत निवासी बुढ़सैनी के साथ लोनी जाने के बारे में पता चला, लेकिन पूछताछ होने से पहले ही विक्रांत एक मुकदमे में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। उधर, हत्या के दस दिन बाद भी खुलासा नहीं होने पर परिवार वालों ने आक्रोश जताया और पुलिस पर लापरवाही नहीं बरतने का आरोप लगाया। इसमें दोघट पुलिस हत्या की घटना खन्नानगर में होने पर वहीं से कार्रवाई होने का दावा कर रही है तो गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया। विशु के चाचा नरेश तोमर ने बताया कि जल्द ही गाजियाबाद के अफसरों से भी मिला जाएगा। एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार उसका शव गाजियाबाद में मिला था मगर यहां भी परिजन आकर मिले थे तो इस मामले में जांच कराई जा रही है।

मुस्लिम छात्र पर हिंदू छात्रों को पेशाब पिलाने का आरोप, केस दर्ज कर पुलिस ने की पड़ताल

- स्कूल प्रधानाचार्य की शिकायत पर आरोपी छात्र के पिता पर एफआईआर
- आरोपी छात्र ने पिता के मोबाइल पर पेशाब पिलाने का देखा नफरती कंटेंट

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत में प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम छात्र द्वारा हिंदू छात्रों को पानी की बोतल पेशाब पिलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने प्राइमरी विद्यालय में हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। दबाव बढ़ता देख चांदीनगर थाना पुलिस ने एक छात्र के पिता के खिलाफ इठर की धारा 196 1बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्कूल के प्रधानाचार्य युद्धवीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

आपको बता दे कि चांदीनगर थाना क्षेत्र के

ढिकोली गांव के एक प्राइमरी स्कूल में 13 तारीख को पेशाब पिलाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने एक हिंदू छात्र को पानी की बोतल में पेशाब पिलाई। इस अमानवीय हरकत ने अभिभावकों और स्थानीय संगठनों में गहरा रोष पैदा कर दिया है। जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी छात्र ने अपने पिता के मोबाइल पर पेशाब पिलाने से जुड़ा नफरती कंटेंट देखा था, जिसके बाद बच्चों ने यह हरकत दोहराई। इसी आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी छात्र समर के पिता जावल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पिता जावल के खिलाफ इठर की धारा 196 और 1बी के तहत कार्रवाई की है। यह धारा समाज में नफरत फैलाने वाले कंटेंट के प्रसार और नाबालिगों को गलत दिशा में ले जाने जैसे मामलों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखती है। यह मामला तब और सुर्खियों में आया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और कठोर कार्रवाई की मांग की। बढ़ते दबाव और प्रधानाचार्य युद्धवीर सिंह की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने अब मामले की विस्तृत पड़ताल शुरू कर दी है।

70 साल में भी वेस्ट यूपी नही बनी हाईकोर्ट बेंच

- अशोक मधुप-

पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने की मांग एक बहुत पुराना और लगातार जारी रहने वाला आंदोलन है। लगभग 70 साल पुरानी यह मांग केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक गहरी पुकार है। इस आंदोलन के कामयाब न होने की खास बात यह है कि आंदोलनरत वकील आदोलन से जनता को नही जोड़ सके। वह यह बताने में और जनता में मन में बैठाने में असफल रहे कि हाईकार्ट की बैंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनने से यहां के रहने वालों को क्या लाभ होगा?

1948 में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर था। वैसे 1955 की विधि आयोग की सिफारिशों ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। आयोग ने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय की बेंच उन क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ से दूरी अधिक है। साल 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूणानंद ने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की। वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने केंद्र को खंडपीठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भेजा । जनता पार्टी के शासन में राम नरेश यादव की सरकार ने भी इस मांग पर मुहर लगाई और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को कर उसे केंद्र सरकार को भेजा। बनारसीदास सरकार एवं बाद में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में भी एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को संस्तुति प्रदान की गईं। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। 1970 और 1980 के दशक में, यह आंदोलन और भी जोर पकड़ने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव और अजित सिंह जैसे नेताओं ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया। इससे यह मांग राजनीतिक मुद्दा बन जरूर बन गई किंतु नेताओं की इच्छा शक्ति के अभाव में और इलाहाबाद के वकीलों के दबाव में कभी पूरी नही हुई। आज भी, पश्चिमी यूपी के कई संगठन और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर नियमित रूप से आंदोलन करते रहते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा से इलाहाबाद की दूरी 500 से 700

किलोमीटर है। इस लंबी दूरी के कारण मुवक्किलों और वकीलों को अत्यधिक समय, धन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। गरीबी और संसाधनों की कमी वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा बोझ बन जाता है। इलाहाबाद में एक मुकदमे के लिए जाने का मतलब है, न केवल यात्रा का खर्च, बल्कि वहाँ रहने और खाने का भी खर्च। इसके अलावा, वकीलों की फीस भी अधिक होती है। यह सब मिलकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय को बहुत महंगा बना देता है। एक बात और इलाहाबाद की जगह यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लखनऊ खंड पीठ से संबद्ध कर दिया जाता, तब भी दूरी दौ सौ किलोमीटर के आसपास कम हो जाती। लखनऊ पश्चिम उत्तर प्रदेश के नजदीक पड़ता है किंतु ऐसा भी नहीं किया गया।इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले से ही मुकदमों का भारी बोझ है। पश्चिमी यूपी से आने वाले मामलों की बड़ी संख्या के कारण, न्याय में और अधिक देरी होती है। एक बेंच की स्थापना से मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, जिससे न्यायपालिका पर दबाव कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अक्सर 'भारत का चीनी का कटोरा' कहा जाता एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से इस क्षेत्र की न्यायिक और राजनीतिक पहचान मजबूत होगी, और यह एक आत्मनिर्भर केंद्र बन सकेगा। वर्तमान में भी यह आंदोलन जारी है, हालाँकि इसने कई बार धीमी गति पकड़ी है। 1981 से वकीलों के संगठन नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को हड़ताल करते हैं, वे धरने देते रहतें हैं, और ज्ञापन सौंपते हैं। हालांकि, इस आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के सामने सबसे बडी चुनौती है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मांग को टालती रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील इस मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बेंच की स्थापना से उनका काम और आय प्रभावित होगी। सरकार का तर्क है कि एक बेंच की स्थापना से प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी और यह एक आर्थिक बोझ होगा। इसके अलावा, सरकार अक्सर इस मुद्दे को भविष्य के लिए टाल देती है। एक मजबूत और एकीकृत नेतृत्व की कमी ने इस आंदोलन को कमजोर किया है। अलग-अलग संगठन अपने-अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, जिससे एकता नहीं बन पाती।

हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापना के लिए सांसद अरुण गोविल मुखर हो गए हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग उठाने के बाद सांसद अब अधिवक्ताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कराएंगे। इसके लिए सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के लिए मिलने का समय मांगा है। सांसद ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ आबादी को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय की चार बेंच हैं।मध्य प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़े होने के बाद भी यहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल है। सांसद ने कहा कि यहां बेंच मिलने से कम समय में न्याय मिलेगा और धन की भी बचत होगी।एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न केवल पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय तक पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि यह पूरे राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा। यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका और सभी हितधारक मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालें। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक नई पीठ ओर राज्य में चौथी हाईकोर्ट बेंच के गठन की अधिसूचना एक अगस्त को जैसे ही जारी हुई यूपी के मेरठ में सरगर्मियां बढ़ गईं। 'पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति' ने तुरंत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के बार अध्यक्षों और महामंत्री के साथ बैठक की. समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से सवाल किया कि जब कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की चौथी बेंच खुल सकती है तो यूपी के मेरठ में हाईकोर्ट की तीसरी बेंच क्यों नहीं स्थापित हो सकती? मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के वकीलों ने चार अगस्त को हड़ताल कर प्रदर्शन किया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना का आंदोलन पिछले लगभग 70 साल से जारी है। कब तक जारी रहेगा, यह भी नही कहा जा सकता।इतना जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 70 साल चलने वाला यह आंदोलन लंबी अवधि तक चलने वाले आंदोलनों में जरूर दर्ज हो गया है।

हाईवे के किनारे खड़ी गाड़ियों पर सुप्रीम टिप्पणी

-डॉ. आशीष वशिष्ठ-

देश भर में नेशनल हाईवे व शहर के अंदर व आउटर में संचालित होटलों, ढाबों के किनारे भारी वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए रोड पर जहां-तहां वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। सड़क किनारे खड़े ऐसे वाहन अन्य वाहन चालकों और यात्रियों के लिए यमदूत साबित हो रहे हैं। बीती 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फालौदी और तेलंगाना के श्रीकाकुलम के सड़क हादसों में 37 लोगों की मौत पर सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए सड़क सुरक्षा की गंभीर खामियों पर चिंता जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हाईवे के किनारे अवैध ढाबों पर भी चिंता जताई। कहा कि इन ढाबों पर आने वालों की गाड़ियां हाईवे पर खड़ी रहती हैं, जिनसे हादसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सड़क किनारे मौजूद ढाबों और सड़क मेंटेनेंस की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर एक सर्वे कराया जाए, जिससे यह पता चल सके कि कितने ढाबे राजमार्गों के किनारे ऐसे क्षेत्रों में बनाए गए हैं जो इस तरह की सुविधाओं के लिए अधिसूचित नहीं है यानी अवैध ढाबों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। यातायात के नियमों के मुताबिक, हाईवे के किनारे सड़क पर ट्रक व अन्य वाहन खड़े नहीं किए जा सकते हैं।

शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी के आलोक में बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के नाम पर हमने सरपट वाहन दौड़ने वाली सड़कें तो बना दी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि यात्रा दुर्घटनाओं से निरापद कैसे रहे। यह हृदय विदारक होता है कि सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों, ट्रकों की अराजकता तथा राजमार्ग के अवरोधों के चलते परिवार के परिवार असमय काल कवलित हो जाते हैं। जिम्मेदार विभाग और सरकार की चतुराई यह होती है कि वह समस्या के मूल में जाने की बजाय जांच और फौरी कार्रवाई में लग जाता है। इन हादसों की जवाबदेही तय नहीं की जाती। हर हादसे के बाद पुरानी तंत्र पुरानी स्क्रिप्ट को दोहराता है।

आमतौर पर किसी भी बड़े हादसे में शिकार हुए यात्रियों की संख्या का ही जिक्र होता है और सरकार मुआवजे की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। अधिक से अधिक हमारे विमर्श का मुद्दा यह होता है कि दोषी कौन था? कौन सा ड्राइवर लापरवाही से वाहन चला रहा था, वह नशे में था या उसे नींद की झपकी लग गई। या फिर वाहन में तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ। लेकिन वास्तव में हम उन तकनीकी व वास्तविक खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। एक ओर जहां सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई चूक होती हैं, वहीं सड़कों के किनारे बेतरतीब बने ढाबे भी होते हैं, जहां अकसर ट्रक चालक अपने वाहन गलत ढंग से खड़े कर देते हैं। लेकिन हर हादसे में कहीं न कहीं ऐसे कारण जरूर होते हैं, जो दुर्घटना की तात्कालिक वजह बनते हैं। लेकिन अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा करने की वजह से भविष्य में ऐसी ही दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की आशंका बलवती होती है।

भारत में सड़क हादसे एक गंभीर चिंता का विषय हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 4,80,583 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,72,890 से अधिक मौतें हुईं और 4,62,825 लोग घायल हुए। देश में प्रतिदिन लगभग 1,316 हादसे और 474 मौतें होती हैं, यानी हर घंटे लगभग 20 जानें जाती हैं। दुनिया के केवल 1 प्रतिशत वाहन भारत में हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वैश्विक मौतों का 11 प्रतिशत हिस्सा यहीं है। यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह-जगह टोल संग्रह केंद्रों के जरिये टैक्स तो खूब वसूले जाते हैं, लेकिन राजमार्गों को दुर्घटनाओं से निरापद बनाने के लिये गंभीर प्रयास नहीं होते। कुकुरमुत्तों की तरह सड़कों का अतिक्रमण करते ढाबों पर लगाम नहीं लगाई जाती। गंभीरता से पड़ताल नहीं होती है कि क्या सड़क निर्माण में ठेकेदार ने सभी तकनीकी मानकों का पालन किया है?

सबसे ज्यादा बड़े वाहन ढाबों पर खड़े नजर आते हैं। रात व दिन में यहां वाहन एक के पीछे एक खड़े रहते हैं। रात के समय तो आलम और भी भयंकर होता है, यहां से निकलने में भी डर बना रहता है। नियमित चेकिंग न होने और चालान न होने की वजह से यहां हादसे का डर बना रहता है। छुटपुट मामले तो आये दिन होते रहते हैं।बरसात के मौसम में इन ढाबों के पास हादसे की अधिक आशंका रहती है। ट्रक मिट्टी में खड़े होकर हाईवे पर आते हैं तो मिट्टी सड़क पर जमा हो जाती है। बरसात में इस मिट्टी से फिसलकर बाइक सवार हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस के अलावा कई बार ट्रकों या अन्य लोडिंग वाहनों में उनकी क्षमता से अधिक माल भरा होता है। मुख्यता लोहे के सरिये, गर्डर आदि जो लोडिंग की लंबाई में न आते हुए पीछे तक निकले रहते हैं। इस तरह के वाहन भी हादसों का कारण बनते हैं।

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से लाखों रुपये रुपये प्रचार-प्रसार पर बहाया जाता है। इसके बावजूद सड़क सुरक्षा के नियम निर्देश कहीं भी धरातल पर देखने को नहीं मिलते हैं। गोष्ठियों और सेमिनारों में तो वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा जाता है लेकिन हाईवे ट्रक, डीसीएम, कंटेनर या अन्य वाहन चालकों को समझाने वाला कोई नहीं है। देश में सैकड़ों लोगों की मौत सड़क के किनारे गलत तरीके से खड़े ट्रक से वाहनों के टकराने से होती है, लेकिन दोषी ट्रक चालक को कड़ी सजा नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को भी गति सीमा में रहने तथा अन्य सावधानियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सरकारों का दायित्व भी बनता है कि राजमार्गों पर रफ्तार की सीमा के नियमन के साथ बाधामुक्त सफर भी सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये नियमित जांच-पड़ताल की जाती रहे। ताकि निर्दोष लोगों के बेमौत मरने का सिलसिला खत्म हो सके। इन विभागों व मंत्रालयों का जिम्मा सिर्फ टोल वसूलना ही नहीं है बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाना भी इनकी जवाबदेही है। निश्चित रूप से सड़क के निर्माण की गुणवत्ता तथा उसे दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये उच्च सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन भी उतना जरूरी है। इसके अलावा सख्त कानून व निगरानी के जरिये ट्रकों व भारी वाहनों को सड़क के किनारे खड़े करने पर रोक लगायी जाए। भारत में हर साल हजारों सड़क हादसे होते हैं. ज्यादातर में लापरवाही जिम्मेदार होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सरकार और अधिकारियों पर दबाव डालेगा। इससे हाईवे सुरक्षित होंगे, ढाबे नियंत्रित जगह पर चलेंगे और ट्रक पार्किंग के लिए अलग जगह बनेगी। आम जनता की जान बचाने के लिए ये बड़ा फैसला साबित हो सकता है।

बड़ा पर्दा

मैं किसी तय नियम या कैलेंडर से नहीं जीती: कुब्रा सैत

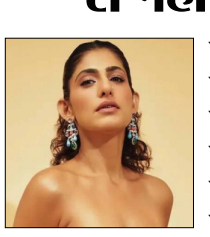

हाल ही में अभिनेत्री कुब्रा सैत 'लव लिंगो' सीजन 2 के पहले एपिसोड में महिलाओं की पहचान और समाज द्वारा बनाए गए नियमों से परे जीने के मायने पर खुलकर बात की। जस सगू और अर्सला कुरैशी द्वारा होस्ट किए जा रहे इस शो का नया सीजन प्रेम, भाषा और संस्कृति के रिश्तों को नए सिरे से समझने का प्रयास करता है, और कुब्रा की ईमानदार बातचीत ने इसे एक सशक्त दिशा दी। कुब्रा ने कहा, "अच्छी लड़कियाँ लड़कों से बात नहीं करतीं, अच्छी लड़कियाँ लिपस्टिक नहीं लगातीं, अच्छी लड़कियाँ बस सुनती हैं बचपन में मैंने कहीं यह पढ़ा था। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी में इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं किसी तय नियम या कैलेंडर से नहीं जीती। कब शादी करनी है या कब खुश रहना है, ये मैं खुद तय करती हूँ। मैंने 30 साल की उम्र में तैरना सीखा, खुले समुद्र में गोता लगाया मेरे लिए यही असली आजादी है।" पिछले सीजन में दीपिका पादुकोण के प्रेरणादायक विचारों की तरह, इस बार कुब्रा सैत ने भी जेंडर आधारित सामाजिक उम्मीदों को चुनौती देते हुए महिलाओं को अपने जीवन के मायने खुद तय करने की प्रेरणा दी। बातचीत के दौरान अर्सला कुरैशी ने 'सैक्रेड गेम्स' में कुब्रा द्वारा निभाए गए किरदार कुकू का ज़िक्र किया, जिसने पर्दे पर जेंडर विविधता का प्रतिनिधित्व किया था। अर्सला ने कहा, "कोई मुंबई इस सोच के साथ नहीं आता कि मैं ट्रांसजेंडर का किरदार निभाकर मशहूर हो जाऊँगा, लेकिन आपने वो कर दिखाया और समुदाय को यह विश्वास दिलाया कि वे जैसे हैं, वैसे ही रहकर भी दुनिया का प्यार पा सकते हैं।"

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ने निकाली ट्रंप की हवा

-सनत जैन-

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब भारतीयों के प्रति नरम पड़ता दिखने लगा है। यह परिवर्तन एक झटके में देखने को मिला है। जब न्यूयॉर्क के मेयर पद पर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के चुने जाने पर उन्होंने जिस तरह से ट्रंप को अमेरिका में चुनौती दी है। उसके कारण ट्रंप को अपने रूप में बदलाव लाना पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 10 महीने में भारतीयों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। टैरिफ में भी भारत को सबसे पहले निशाने पर लिया। ट्रंप ने अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से निकालते वक्त हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर भारत वापस भेजा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उन्होंने भारत के प्रति जो रुख इख्तियार किया था, वह एक तरह से भारत को नीचा दिखाने वाला काम ही था। न्यूयॉर्क सहित दो अन्य राज्यों में जिस तरह से ट्रंप को पराजय का सामना करना पड़ा है, उसके बाद ट्रंप को समझ आ गया है, कि भारत के खिलाफ वह जो कार्रवाई कर रहे हैं। वह अमेरिका के लिए हितकारी नहीं है। जिस तरह से न्यूयॉर्क के मेयर ने चुने जाने के तुरंत बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत की नीतियां जिसमें समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद तीनों शामिल था उसके आधार पर अमेरिका के नागरिकों को अधिकार देने की बात कही। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कहा। उसके बाद से ही ट्रंप के रुख में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ट्रंप ने दो हफ्ते में दूसरी बार ट्रेड डील और टैरिफ को कम करने के बारे में बयान दिया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियों गौर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात कही। ट्रंप ने कहा, भारत कभी भी अमेरिका के कंज्यूमर प्रोडक्ट का बाजार नहीं रहा है। अमेरिका खुद चीन से कंज्यूमर प्रोडक्ट मांगता है। ऐसी स्थिति में हम भारत के साथ जल्द ही ऐसे संबंध स्थापित कर रहे हैं जिसे भारतीय मुझसे फिर प्यार करने लगेंगे। भारत की तारीफ करते हुए ट्रंप यहां तक कह दिया कि दुनिया की सबसे तेज आर्थिक गति से बढ़ता हुआ मध्यम वर्गी देश है। हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक साझेदार है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के संबंध भारत से बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। पिछले 10 महीने में जो तनाव देखने को मिला था वह जल्दी ही दूर हो जाएगा। एक बार फिर भारत और अमेरिका के बीच प्यार परवान चढ़ेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरिया बदला है, उससे भारत की मुसीबतें कम होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय प्रवासियों एवं छात्रों के लिए जिस तरह की नीतियां अमेरिका ने बनाई थीं उसमें भारी शुल्क लगाया था। तरह-तरह की शर्तें लगाई गईं थीं। निश्चित रूप से उसमें अब भारत को राहत मिलेगी। भारत और अमेरिका के एक बार फिर बेहतर संबंध स्थापित होंगे। अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों तथा अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय काम कर रहे हैं उन्हें भी ट्रंप के इस बदले हुए रुख से राहत मिलेगी। ट्रंप ने जो कहा है, यदि वास्तव में वह भारत के प्रति इस तरह का रुख बदलेंगे तभी इस पर विश्वास होगा। जिस तरह से पिछले 10 माह में ट्रंप पहले कोई बात कहते हैं। बाद में मुकर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत गंभीर व्यक्ति नहीं माना जा रहा है। अमेरिका में जो बदलाव देखने को मिले, 40 दिन से अधिक शटडाउन लगा रहा। अब जाकर अमेरिकी सीनेट ने बजट पास किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर साइन किए हैं। इससे पहले लाखों लोग नौकरी से बाहर हो गए। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप की छवि लगातार खराब हो रही थी, जिसे देखते हुए ट्रंप में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह समय की मांग है। 27 नवंबर से अमेरिका में थेंक्स गिविंग फेस्टिवल शुरू हो जाता है। छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इस माह के अंत तक या अगले साल की जनवरी माह तक अमेरिका से भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत के माध्यम से एशिया महाद्वीप में बेहतर संतुलन बनाने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। देर आयद, दुरुस्त आयद की तर्ज पर ट्रंप यदि अपनी बातों पर कायम रहे तो निश्चित रूप से भारत के साथ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध बेहतर होंगे। यही दोनों देशों के हित में है। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष, ट्रंप और मोदी एक दूसरे को सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। अब दोनों को यह साबित करने का एक नया मौका होगा।

ऋण के जाल में फंसे देशों से भारत के राज्यों को मिलती है सीख

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं - जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)।

ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था। भारत में भी कुछ राज्य ह्लफ्रीबीह्व के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है। सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किश्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोक लुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है। वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी आर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है। अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे हैं और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा ररही हैं। इस प्रकार ये राज्य ह्लडेट ट्रैपह्व की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पूंजीगत खर्च नहीं कर रहे हैं तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है। विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने जंतर मंतर पर मनाया यादव शौर्य दिवस

नई दिल्ली। दिल्ली के जन्तर मन्तर पर रविवार को अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के द्वारा यादव शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेन्द्र यादव ने बताया कि 1962 भारत-चीन रेजांगला युद्ध 114 वीर अहीर जवानों के शौर्य पराक्रम, शहादत व बलिदान के सम्मान में भारतीय सेना में अहीर रेजीमेंट निर्माण, सम्मान समारोह व यादव शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से सेना में अहीर रेजीमेंट गठन की मांग भी गई। श्री यादव ने यह भी मांग की है कि '120 बहादुर फिल्म' का नाम '120 वीर अहीर' किया जाये।

इस मौके पर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखें। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी टीसी राव के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष राजबहादुर यादव, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव, राष्ट्रीय महासचिव जीडी यादव, रासबिहारी मंडल, प्रमोद कुमार, पारस यादव, साहिल यादव, अश्वनी यादव, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जितेन्द्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश बंशीधर यादव, धर्मराज यादव, राजस्थान प्रदेश महिला की अध्यक्ष सुषमा यादव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष डॉ. शशि यादव, राष्ट्रीय महासचिव रजनी यादव, सीमा यादव, संजय यादव, रमेश यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा वॉकथॉन का आयोजन किया गया

यातायात जागरूकता माह में जनप्रतिनिधियों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने बढ़ाया कदम

गाजियाबाद। शहर में यातायात जागरूकता माह के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार सुबह 'सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा' थीम पर एक वॉकथॉन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना, सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों को बढ़ावा देना और सड़कों पर बढ़ रहे हादसों में कमी लाना था। वॉकथॉन सुबह करीब 8 बजे कविनगर रामलीला मैदान से शुरू हुआ, जिसमें शहरभर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आम नागरिकों के साथ सांसद, विधायक, नगर आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और कई विभागों के अधिकारी भी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाते चले। कार्यक्रम के दौरान गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि इन छोटे-छोटे नियमों से अनगिनत हादसों को रोका जा सकता है। वॉकथॉन में एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र, कॉलेजों के युवा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े पोस्टर व स्लोगन के साथ लोगों को नियमों का पालन करने का संदेश दिया। मंच से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, ओवरस्पीडिंग से बचने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने जैसे नियमों पर विशेष जोर दिया गया। कविनगर मैदान में स्कूली बच्चों और युवा कलाकारों ने सड़क हादसों पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत किए, जिनमें दिखाया गया कि कुछ सेकंड की लापरवाही कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। वॉकथॉन में शामिल खिलाड़ियों, समाजसेवियों और स्थानीय कलाकारों ने भी मंच से लोगों को जागरूक किया। लोकगायकों और खेल जगत से जुड़े प्रतिभागियों ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को खतरे में डालना है।

गाजियाबाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मातृ मृत्यु कम करने के लिए नई मुहिम शुरू

गाजियाबाद। जनपद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी से जुड़ी मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की शुरूआत की है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा प्रतिदिन उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का हाल-चाल लिया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पहल को धरातल पर उतारने के लिए विशेष निगरानी टीमों का गठन किया गया है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं की डिलीवरी के पश्चात नवजात के स्वास्थ्य का भी फॉलो अप लिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच गाजियाबाद में कुल 4,945 हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी। शहरी क्षेत्र में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि में शहरी क्षेत्र में 3 हजार 666 गर्भवती महिलाएं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1279 हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं चिन्हित हुई हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में बड़ी संख्या में महिलाएं उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में है। जिन्हें समय-समय पर

देखभाल और निरंतर चिकित्सीय निगरानी की आवश्यकता होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भवती मां और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, पहले प्रसव में जटिलताएं, कम वजन, अत्यधिक उम्र और मधुमेह के चलते हाई रिस्क प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाओं का प्रतिदिन हाल-चाल पूछने और विशेष स्तर पर निगरानी करने से मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन के मुताबिक सभी स्वास्थ्य इकाइयों में तैनात चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्रतिदिन फोन कॉल के माध्यम से हाल-चाल लिया जाएगा। सभी चिकित्सा इकाइयों में टीमें बनाई गई है जो मातृ स्वास्थ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं से फोन कर बातचीत करेंगे और उनके स्वास्थ्य का नियमित फॉलो अप करेंगी। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो समय-समय पर अस्पताल लाकर दिखाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच गाजियाबाद में 27 मातृ मृत्यु दर्ज हुई है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 10 मातृ मृत्यु दर्ज हुई। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस पहल से समय पर गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली देखभाल से मां और नवजात दोनों का जीवन सुरक्षित रखा जा सकेगा। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन के मुताबिक, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने पर डिलीवरी के दौरान कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बनी रहती है। जिले की सभी सरकारी चिकित्सा इकाइयों में आने वाली गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की जाती है। अब जिले में हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं का स्वास्थ्य विभाग द्वारा रस हाल-चाल पूछा जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने चोरी व खोए मोबाइल फोन मालिकों को सौंपे

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन में से 47 बरामद किए। उनमें से 20 फोन को रविवार को विशेष वितरण समारोह में उनके असली मालिकों को सौंपा गया। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने टीम की कड़ी मेहनत और संयुक्त प्रयासों की सराहना की। बताया कि उनके समर्पण और लगातार फील्डवर्क ने यह सुनिश्चित किया कि खोए हुए मोबाइल फोन सही समय पर अपने मालिकों तक पहुंच सके। डीसीपी ने बताया कि इंस्पेक्टर उमेश सती और एसीपी कैलाश शर्मा की देखरेख में महिला कांस्टेबल पूजा, महिला कांस्टेबल सिमरन, महिला कांस्टेबल अलका और महिला कांस्टेबल पूजा की एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने पिछले महीने 47 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए। ये मोबाइल फोन टीम के समर्पित और अथक प्रयासों से बरामद किए गए। उनके निरंतर फील्डवर्क, तकनीकी विश्लेषण और समन्वित अनुवर्ती कार्रवाई ने इस रिकवरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दिल्ली में मेट्रो साइट से 15 लाख की तांबा केबल चोरी में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मेट्रो निर्माण स्थल से 15 लाख रुपये मूल्य की लगभग 1,200 मीटर तांबे की केबल चोरी करने के आरोप में एक आदतन अपराधी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी राजा बंठिया ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने केबल को ट्रक पर लाद लिया तथा दो-तीन नवंबर की दरमियानी रात को वहां से भाग गए। निर्माण कंपनी में पर्यवेक्षक के रूप में काम करने वाले शिकायतकर्ता देव सिंह ने सामग्री गायब होने का पता चलने पर ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच के दौरान, पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की। फुटेज में दो लोग चोरी की केबल को एक ट्रक पर लादते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक की पहचान घटनास्थल पर क्रेन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे रणधीर सिंह के रूप में हुई। तकनीकी निगरानी के आधार पर, सिंह के मोबाइल के माध्यम से अमृतसर में स्थित उसके पैतृक गांव में होने का पता चला। पुलिस की एक टीम ने आठ नवंबर को वहां छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि सिंह (29) पहले भी लुधियाना में हुई हत्या और राजस्थान के उदयपुर में एक एटीएम मशीन चोरी समेत चार आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पूछताछ के दौरान सिंह ने कथित तौर पर अपने सहकर्मी पंकज कुमार की संलिप्तता का खुलासा किया।

गाजियाबाद में साइबर सेल ऑनलाइन ठगी मामलों में पीड़ितों को लौटाए रूपए

गाजियाबाद। जिले में पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी के दो मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को कुल 80,000 रुपए वापस दिलाए हैं। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक और थाना कौशांबी की टीमों ने तकनीकी जांच और बैंक समन्वय के जरिए यह राशि सुरक्षित रिफंड कराई। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के प्रवीण त्यागी ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर 25,000 रुपए की ठगी का शिकार हुए थे। शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर मिलते ही साइबर सेल ने तुरंत बैंक खाते को ट्रेस किया, ट्रांजैक्शन होल्ड कराया और पूरी प्रक्रिया पूरी कर पीड़ित को पूरी राशि वापस दिलाई। दूसरा मामला थाना कौशांबी क्षेत्र का है, जहां सेक्टर-01 वैशाली निवासी रवि सिंह का मोबाइल फोन हैक कर उनके बैंक खाते से 55,000 रुपये निकाल लिए गए। साइबर सेल की जांच में संदिग्ध खाते का पता लगाया गया और बैंक से तत्काल संपर्क कर राशि रोक दी गई। निरंतर समन्वय के बाद 16 नवंबर 2025 को रवि सिंह को उनके 55,000 रुपये वापस मिल गए। दोनों ही मामलों में साइबर सेल की तेजी और तकनीकी दक्षता से ठगी गई रकम समय पर रिकवर हो सकी। पीड़ितों ने पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि या साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत एनसीआरपी पोर्टल (1930 हेल्पलाइन) पर शिकायत दर्ज कराएं।

दिल्ली पुलिस के बेड़े में 55 पीसीआर वैन और 156 मोटरसाइकलें शामिल, वाहनों से रिस्पॉन्स टाइम घटेगा

नई दिल्ली। राजधानी में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 55 नई पीसीआर मोबाइल पेट्रोल वैन (एमपीवी) और 156 रिफर्बिश्ड ओम्नी मोटरसाइकिलों को बेड़े में शामिल किया है। जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय पर आयोजित फ्लैग-आफ समारोह में पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री गोलचा ने कहा कि नई पीसीआर वैन और मोटरसाइकिलों की तैनाती से दूरदराज, संकरी गलियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी व पहुंच दोनों में तेजी आएगी। इससे न सिर्फ शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी बल्कि पीसीआर यूनिट की दृश्यता और प्रभाव भी बढ़ेगा। 55 नई पीसीआर वैन को द्वारका, आउटर नॉर्थ, साउथ, साउथ-वेस्ट, रोहिणी, आउटर और साउथ-ईस्ट जिलों में भेजा गया है। यह वितरण उन इलाकों में पुलिस मूवमेंट और कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है जहां घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया बेहद जरूरी मानी जाती है। वहीं, भीड़भाड़ और संकरी गलियों में बेहतर गश्त और तुरंत हस्तक्षेप के लिए पीसीआर यूनिट ने 156 रिफर्बिश्ड ओम्नी मोटरसाइकिलों को फिर से तैनात किया है। ये संवेदनशील इलाकों में उपस्थिति बढ़ाने और पीक-आवर में तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पीसीआर वैन का बेड़ा 857 हुआः नई वैन शामिल होने के बाद पीसीआर बेड़े की कुल संख्या 802 से बढ़कर 857 हो गई है। इसे दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण, ऑपरेशनल दक्षता और नागरिक-हितैषी पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि पीसीआर दिल्ली पुलिस की वह इकाई है जो राजधानी में संकट, आपात स्थिति और अपराध की सूचना मिलने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचती है। 24 घंटे तैनात यह यूनिट फील्ड सपोर्ट, गश्त, अपराध रोकथाम और त्वरित कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे पुलिस का काम और आसान होता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक विनोद कुमार यादव द्वारा उजाला प्रिन्टिंग प्रेस सी-3, मौजपुर सब्जी मंडी, दिल्ली-53 से मुद्रित एवं डी-1/1146, गली-28, हर्ष विहार दिल्ली-93 से प्रकाशित। RNI NoÜ: DELHIN/2012/51663 सम्पादकः राजेश यादव (मोः 9212526181)
अपनी खबरें/लेख सामग्री पर Email: jantantralive@gmailÜcom भेजें। नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी लेख/समाचार से संबंधित विवाद का निपटारा दिल्ली क्षेत्र में मान्य होगा। समाचार पत्र में समस्त पद अवैतनिक हैं।